● वर्ष-3
● अंक-114
रायपुर, गुरुवार
21 दिसंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› सर्दियों में खाएं ये गर्म....

भारत में कोरोना के नए सब-वैरिएंट के 21 एक्टिव केस

अब तक 40 देशों में फैल चुका है जेएन.1

नई दिल्ली। कोरोना वायरस का नया सब-वैरिएंट भारत में भी दस्तक दे चुका है. अब भारत के तमाम राज्यों में इससे होने वाले इन्फेक्शन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. अब तक कोरोना के सब-वैरिएंट जेएन.1 के 21 मामले सामने आ चुके हैं. इनमें से 19 केस की गोवा में पहचान की गई है, जबकि एक-एक मामले केरल और महाराष्ट्र में पाए गए हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, कोविड का नया सब-वैरिएंट अब तक 40 देशों में फैल चुका है. इस नए सब-वैरिएंट की खासियत ये है कि ये दूसरे स्ट्रेन की तुलना में तेजी से फैलता है. सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के सदस्य (हेल्थ) वीके पॉल ने बुधवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि नए सब-वैरिएंट के एक्टिव मामलों में 92.8 प्रतिशत मामले होम-आइसोलेशन के हैं, जो हल्की बीमारी का संकेत देते हैं. कोविड के कारण अस्पताल में भर्ती होने की दर में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है. वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सब-वैरिएंट छह.1 को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्कता बरतने को कहा है. स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को देशभर में स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने कोरोना वायरस के उभरते सब-वैरिएंट को लेकर सतर्क रहने पर जोर दिया. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, इस समय सतर्क रहना और कोरोना वायरस के नए और उभरते स्ट्रेन के खिलाफ तैयार रहना महत्वपूर्ण है. उन्होंने कोविड के नए स्ट्रेन को रोकने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच को-ऑर्डिनेशन की जरूरत पर जोर दिया. स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, आइए हम केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर हर तीन महीने में एक बार मॉक ड्रिल करें. अच्छे प्रयासों को साझा करें.

गुड गवर्नेंस के लिए प्रतिबद्ध सरकार- राज्यपाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही कल यानी गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब राज्यपाल के अभिभाषण और द्वितीय अनुपूरक बजट पर गुरुवार को ही चर्चा की जाएगी। इससे पूर्व प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने अभिभाषण दिया। इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने सदन पटल पर दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया।

शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र का अभिभाषण हुआ। उन्होंने जैसे ही इंग्लिश में भाषण पढ़ना शुरू किया, जिस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने टोका। सवाल उठाते हुए कहा कि कहा कि सदन में इंग्लिश पढ़ने वाले कम हैं। आपका पढ़ा हुआ हम समझ लेंगे। ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे। इसके बाद सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच हल्की-फुल्की बहस भी हुई। फिर राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सीएम

दूसरा अनुपूरक बजट पेश

साय सहित कई विधायकों ने धन्यवाद प्रस्ताव लाया।

सीएम ने अपने विधायकों का परिचय सदन से करवाया। इसके बाद विपक्ष ने प्रदेश के किसानों की आत्महत्या की खबर पर सवाल दागे। पक्ष ने जवाब दिया तो जमकर हंगामा हुआ। सदन में जय-जय श्री राम और छत्तीसगढ़ महतारी की जय के नारे लगे। इसके साथ ही गुरुवार तक के लिए सदन स्थगित हो गई। राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन में अभिभाषण में नई सरकार को बधाई देते हुए कहा कि आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। आपने जो वादा और दवा किया है उसे आप पूरा करें। मतदान के प्रतिशत का दूरस्थ इलाकों में बढ़ना, सरकार के विश्वास को बताता है। लोगों का संविधान के प्रति लगाव को बताने के लिए काफी है। इसके साथ ही कहा कि मेरी सरकार अपने योजनाओं को पूरा करे। सदन की जो परंपरा है, उसे उच्च स्तर पर लेकर जाएं। पक्ष और विपक्ष दोनों के भावनाओं का पूरा सम्मान हो। मेरी सरकार गुड गवर्नेंस को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार ने 18 लाख आवास के वादा को पूरा किया है। मेरी सरकार दो साल का बकाया बोनस देने का वादा पूरा करने जा रही है। राज्यपाल ने कहा कि अटल जी और मोदी जी के सपनों को हमारी सरकार साकार करेगी। दो साल का बकाया बोनस और प्रधानमंत्री आवास देने का अपना वायदा पूरा करेंगे। हमारी सरकार पीएससी की नौकरी में पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल के अभिभाषण पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कृतज्ञता प्रस्तुत किया। इसका पुन्नलाल मोहले ने समर्थन किया। अब गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। शीतकालीन सत्र के आखिरी और तीसरे दिन अनुपूरक बजट के अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। मतदान और विनियोग विधेयक पर पुनर्स्थापन होगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद सरकारी काम निपटाए होंगे। (विस्तृत समाचार पेज 3 पर)

नंदकुमार साय ने दिया इस्तीफा

भाजपा छोड़कर कांग्रेस में हुए थे शामिल

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के करारी शिकस्त के बाद पार्टी में इस्तीफों का दौर चल रहा है। अब इसी क्रम में दिग्गज आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव से ठीक पहले नंद कुमार साय ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था, लेकिन पार्टी ने नंद कुमार साय को चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया। साथ ही चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई। ऐसे में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही साय ने मौके का फायदा उठाया है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि साय फिर से अपने पुराने घर यानी बीजेपी में आ सकते हैं। यानी बीजेपी में प्रवेश कर सकते हैं।

30 अप्रैल को दिया था इस्तीफा

30 अप्रैल को साय ने बीजेपी से इस्तीफा दिया था। पार्टी के सभी दायित्वों से खुद को अलग कर लिया था। 1 मई 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस में प्रवेश किए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे लोगों के साथ रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी को फॉलो करता था। अटल-आडवाणी के दौर की जो बीजेपी थी, वो पार्टी अब उस रूप में नहीं रह गई है। परिस्थितियां बदल चुकी हैं। पूर्व सीएम बघेल की उपस्थिति में साय ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस में शामिल हुए थे। फिर वो कांग्रेस के सभी बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करते रहे। सरकारी कार्यक्रमों में भूपेश बघेल के साथ दिखते रहे। साय को छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का चेयरमैन बनाया था, लेकिन राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही साय ने बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को अपना इस्तीफा सौंप दिया है।

कर सकते हैं बीजेपी ज्वॉइनिंग

साय ने अपने इस्तीफा में लिखा है कि कुछ समय पहले किन्हीं स्थितियों के कारण मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, कुछ दिनों तक पार्टी में रहकर निष्ठापूर्वक कार्य भी किया। मेरे सामने जो परिस्थितियां उपस्थित हुई है, उसे देखकर मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्य से त्याग पत्र दे रहा हूं। साय ने कांग्रेस में रहते हुए सीएम विष्णुदेव साय को बधाई देने गए थे। माना जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान से अनुमति मिलने के बाद साय बीजेपी का दामन थाम सकते हैं।

'कांग्रेस तो डूबती नैया है': साय

वरिष्ठ आदिवासी नेता नंदकुमार साय के इस्तीफे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस तो डूबती नैया है। हारे हुए प्रत्याशी कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं। अमरजीत भगत के जासूस वाले बयान पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमसे वरिष्ठ हैं हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने के कयासों पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह तो प्रदेश अध्यक्ष जी ही बताएंगे। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएम विष्णुदेव साय 22 दिसम्बर को दिल्ली जाएंगे। 22 और 23 दिसम्बर को भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं की बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव, विकसित भारत संकल्प अभियान सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी है। मंत्रिमंडल को लेकर भी हाईकमान के नेताओं से चर्चा सम्भव है। नंदकुमार साय के कांग्रेस से इस्तीफा देने पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि नंदकुमार साय को मोदी-नड्डा कांग्रेस भेजे थे। रणनीति के तहत नंदकुमार साय को कांग्रेस भेजे। भाजपा का मिशन 2023 कंप्लीट हो चुका है। इसलिए अब नंदकुमार साय भाजपा जा रहे हैं।

महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र हुआ का समापन, 17 विधेयकों को दी गई मंजूरी

नागपुर। महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र सात दिसंबर को यहां शुरू हुआ और इसका बुधवार को समापन हो गया। सत्र के दौरान विधानसभा ने 17 विधेयकों को मंजूरी दी। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि विधानमंडल का अगला सत्र 26 फरवरी से मुंबई में होगा। उन्होंने कहा कि दो सप्ताह के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा ने 110 घंटे काम किया, जिसका दैनिक औसत 10.05 घंटे था। नार्वेकर ने कहा कि विधानसभा को 7,581 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें से 247 स्वीकार किए गए। उन्होंने कहा कि लगभग 34 सवालों के जवाब दिए गए। उन्होंने कहा कि विधानसभा ने सत्र के दौरान 17 विधेयकों को मंजूरी भी दी। उन्होंने कहा कि 288 सदस्यीय निचले सदन में अधिकतम 93 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम उपस्थिति 64.71 प्रतिशत थी।

प्रमुख समाचार

जब किसानों को नक्सलवादी और उग्रवादी बताया गया तो क्या यह अपमान नहीं था

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी के 'मिमिक्री' किए जाने से जुड़े विवाद की पृष्ठभमि में बुधवार को कहा कि जब आंदोलनकारी किसानों को उग्रवादी तथा नक्सलवादी कहा गया तो क्या यह किसानों का अपमान नहीं था। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद परिसर में उनकी, तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद द्वारा नकल उतारे जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उच्च सदन में कहा कि संसद परिसर में उनकी नकल उतारकर किसान समाज और उनकी जाति (जाट) का अपमान किया गया है। राज्यसभा सदस्य सुरजेवाला ने एक बयान में कहा, ''जब किसान आंदोलन में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत देश के अन्य राज्यों के किसानों को मोदी सरकार के लोग उग्रवादी, नक्सलवादी और अराजक तत्व बता रहे थे तो क्या ये किसानों का अपमान नहीं था?

बंबई उच्च न्यायालय ने दल-बदल कानून में विलय पर संरक्षण को चुनौती पर केंद्र से जवाब मांगा

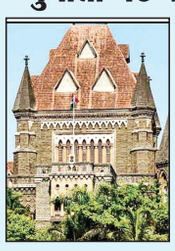

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने दो दलों के आपस में विलय कर लेने की स्थिति में दल-बदल कानून के तहत उन्हें अयोग्य करार दिये जाने से प्राप्त संरक्षण को एक जनहित याचिका के माध्यम से दी गयी चुनौती पर बुधवार को सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने महान्यायवादी आर वेंकटरमनी को भी नोटिस जारी किया क्योंकि जनहित याचिका में संविधान की दसवीं अनुसूची के चौथे अनुच्छेद की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गयी है। दसवीं अनुसूची दल-बदल कानून से संबंधित है। यह प्रावधान कहता है कि दो दलों के आपस में विलय कर लेने की स्थिति में दल-बदल के आधार पर (उन्हें) अयोग्य नहीं करार दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय मीडिया एवं विपणन पेशेवर तथा गैर सरकारी संगठन वनशक्ति की संस्थापक न्यासी मीनाक्षी मेनन की जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा था।

कांग्रेस की मप्र विस में नेहरू की तस्वीर लगाने की मांग

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाने को लेकर हुए विवाद के बीच, नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि सदन में महान नेताओं की तस्वीरें लगाने के बारे में निर्णय लेने के लिए विधायकों की एक समिति गठित की जाएगी। कांग्रेस नेहरू की तस्वीर हटाने को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साध रही है। विधानसभा अध्यक्ष के आसन के पीछे नेहरू की तस्वीर लगी थी और जुलाई में इस तस्वीर को हटाकर संविधान निर्माता डॉ.बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की तस्वीर लगा दी गई थी। बुधवार को कार्यवाही शुरू होने के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार और कांग्रेस के अन्य विधायकों ने यह मुद्दा तब उठाया, जब राज्यपाल मंगूभाई पटेल अभिभाषण दे रहे थे। सोलहवीं मध्यप्रदेश विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हो गया। सिंघार ने मांग की कि सदन में नेहरू की तस्वीर फिर से लगाई जाये क्योंकि वह देश के एक कद्दावर नेता थे और उन्होंने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

सोनिया, राहुल, ममता और खड़गे जी चुप क्यों? देश से त्वरित माफ़ी मांगें: ठाकुर

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज संसद भवन परिसर के बाहर संवाददाताओं से वार्तालाप करते हुए विपक्ष द्वारा लगातार हंगामा कर संसद नहीं चलने दिए जाने व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ठाकुर ने कहा, हालिया चुनावों में मिली पराजय से विपक्ष हताश और निराश है। इंडी अलायंस के नेताओं द्वारा उपराष्ट्रपति जी का अपमान उनकी बौखलात, अहंकार और संविधान विरोधी मानसिकता का प्रमाण है। राहुल गांधी जी ने स्वयं इस कुकृत्य को एंप्लीफाई करने का कार्य किया है। ये केवल उप राष्ट्रपति जी का नहीं बल्कि उनके पूरे समाज, संविधान व देश का अपमान है। देश इसे कतई स्वीकार नही करेगा। विपक्ष लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है। विपक्ष का काम संविधान का अपमान करना है। उपराष्ट्रपति जी के पक्ष में अब लोग सामने आ रहे है। सड़कों पर आ रहे हैं।

नल व्यापारी पर बेखौफ गोली चलाने वाली अमन गिरफ्तार

रायपुर। लाभांडी इलाके में एक बदमाश ने दिनदहाड़े नल व्यापारी पर फायरिंग कर दी जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस की सूचना मिलते ही तेलीबांधा पुलिस एक्शन मूड में आई और चंद घंटों के भीतर ओडिशा से आए आरोपी अमन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। घटना सुबह 11.30 बजे की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेलीबांधा थाना क्षेत्र के लाभांडी में बुधवार सुबह 11ः30 बजे गोली चलने की एक घटना घटित हुई जिसमें आरोपी अमन शर्मा ने नल व्यापारी संदीप कुमार पर अचानक से फायरिंग कर दी। फायरिंग में संदीप के सीने में गोली जा लगी वह लहूलुहान हालत में वहीं गिर पड़ा। दिनदहाड़े गोली चलने की आवाज से वहां पर हड़कंप मच गया और घायल संदीप को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलते ही तेलीबांधा पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चंद घंटों में ओडिशा के सुंदरगढ़ से आए आरोपी अमन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया।

लोकसभा में पास हुए 3 नए क्रिमिनल बिल, राजद्रोह कानून खत्म

नए भारत का नया कानून, मोदी मिटा रहे गुलामी के निशान

नई दिल्ली। लोकसभा में 3 नए क्रिमिनल बिल पास हो गए हैं. आपराधिक संशोधन विधेयकों पर चर्चा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब के दौरान विपक्ष के कुल 97 सांसद अनुपस्थित रहे. इन्हें निलंबित किया गया है. नए क्रिमिनल बिलों को अब राज्यसभा में रखा जाएगा. वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त में पांच प्रण दिए थे। उसमें उन्होंने कहा था कि गुलामी की जितनी भी निशानियां हैं उससे मुक्ति पाना सबसे पहले काम है। गुलामी की सबसे बड़ी निशानी होने का ठप्पा आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंश एक्ट पर था। 1830, 1856, 1872 उस दौरान इन सब चीजों को लाया गया और हम अब तक ढो रहे थे। आईपीसी का असल में नाम आयरिश पीनल कोड था। ये बात तो सभी जानते हैं कि अंग्रेज हिन्दुस्तान की जनता को सहूलियत देने के लिए कानून नहीं बनाते थे। किस तरह से हम सभी को सिस्टम के प्रति एक गुलाम की तरह ट्रीट करे। संविधान तो तैयार कर लिया गया लेकिन अपराध और अपराधियों को पकड़ने का सिस्टम अंग्रेज के जमाने से था। एक शख्स था थोमस बैबिंगटन मैकाले ये भारत तो आया था अंग्रेजी की पढ़ाई करने लेकिन उसके बाद इसी भारत में अगर किसी ने देशद्रोह का कानून ड्राफ्ट किया तो वो लार्ड मैकाले ही था। लेकिन भारत के गृह मंत्री ने ऐसा काम किया है। गुलामी की जंजीरों से पूरे सिस्टम को आजादी दी है।

मॉब लिंचिंग के लिए मृत्युदंड

शाह ने संसद को यह भी बताया कि केंद्र मॉब लिंचिंग के मामलों में मौत की सज़ा का प्रावधान लागू है। जब पांच या अधिक व्यक्तियों का एक समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर हत्या करता है तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। नए प्रावधान में कहा गया है कि आजीवन कारावास या सात साल से कम की कैद नहीं होगी और जुर्माना भी देना होगा।

धर्म छुपाकर शादी करने वाला जेल जाइएगा

इस विधेयक में महिलाओं के खिलाफ अपराध और उनके सामने आने वाली कई सामाजिक समस्याओं का समाधान किया गया है। प्रस्तावित कानून में पहचान छिपाकर किसी महिला से शादी करने के अलावा रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे के तहत महिलाओं के साथ

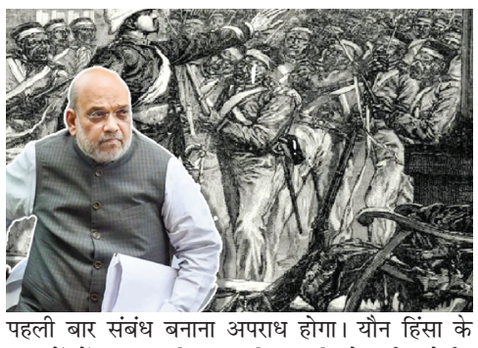

पहली बार संबंध बनाना अपराध होगा। यौन हिंसा के मामलों में बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट ही करेगी। गैंगरेप के मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा।

लोकसभा ने बुधवार को तीन संशोधित आपराधिक कानून विधेयक पारित किए, जिनका उद्देश्य देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करना और भारतीय सोच पर आधारित न्याय प्रणाली स्थापित करना है। विधेयक में भारतीय न्याय संहिता भारतीय दंड संहिता को बदलने का प्रस्ताव करती है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपराधिक प्रक्रिया संहिता को बदलने का प्रयास करती है और भारतीय साक्ष्य संहिता भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेती है। लोकसभा में विधेयकों को पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मौजूदा आपराधिक कानून न्याय प्रदान करने के बजाय दंडित करने के इरादे से औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाते हैं। अमित शाह ने कहा कि भारतीय दंड संहिता का उद्देश्य दंड देना था, न्याय नहीं; इसके स्थान पर भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023 सदन से पारित होने के बाद देश में लागू होगी। गृह मंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानून विधेयक संविधान की भावना के अनुरूप हैं।

लोकसभा में 3 नए क्रिमिनल बिल पर जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- अंग्रेजों के समय का राजद्रोह कानून खत्म किया गया है. नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग जैसे क्राइम में फांसी की सजा दी जाएगी. 3 नए क्रिमिनल बिल के लोकसभा में पास होते ही सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तीन आपराधिक कानूनों के स्थानों पर लाए गए विधेयक गुलामी की मानसिकता को मिटाने और औपनिवेशिक कानूनों से मुक्ति दिलाने की नरेन्द्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं. शाह ने भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए ये भी कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार रूपी तीन सिद्धांत के आधार पर ये प्रस्तावित कानून लाए गए हैं.

पुलिस की जवाबदेही होगी तय

अमित शाह ने कहा- नए कानून में अब पुलिस की भी जवाबदेही तय होगी. पहले किसी की गिरफ्तारी होती थी, तो उसके परिवार के लोगों को जानकारी ही नहीं होती थी. अब कोई गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी. किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ, इसकी जानकारी पुलिस पीड़ित को देगी.

तीनों बिल पीएम मोदी के विजन का हिस्सा

अमित शाह ने कहा, ये तीनों क्रिमिनल कानून पीएम मोदी के विजन का हिस्सा हैं. जनता मांग करती थी कि हमें सजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए. मोदी जी के नेतृत्व में आज हम वो कर रहे हैं. जब हम न्याय कहते हैं, तो इसमें बड़े पैमाने पर ध्यान जाता है. इसमें पीड़ित और आरोपी दोनों आ जाते हैं.

कस्टम मिलिंग के चावल में बड़ी हेराफेरी

गौरेला पेंड्रा मरवाही। सहायक खाद्य अधिकारी ने सोमवार देर रात पेट्रोल पंप में संदिग्ध अवस्था में खड़े चावल लोड ट्रक को पकड़ा। पूछताछ में ड्राइवर ने कोरबा के कटघोरा के मातेश्वरी राइस मिल के नाम का दस्तावेज दिखाया। जिसे वह बिलासपुर के करगी रोड कोटा के एफसीआई गोदाम में जमा करने जा रहा था। खाद्य अधिकारी को मामले में गोलमाल लगा और चावल से भरे ट्रक को जब्त कर लिया।

खाद्य अधिकारी ने चावल से भरे ट्रक को कब्जे में लेकर ड्राइवर से पूछताछ शुरू की। ड्राइवर ने बताया कि उसने यह चावल गौरेला के अंजनी औद्योगिक केंद्र स्थित जेपी अग्रवाल राइस मिल के गोदाम से लोड किया है। जिसे एफसीआई करगीरोड में खाली करना है। पूरा मामला संदिग्ध मानकर सहायक खाद्य अधिकारी ने ट्रक को थाने में खड़ा कर दिया। खाद्य विभाग इस पूरे मामले पर गुपचुप तरीके से जांच कर रहा है। हालांकि प्रशासन की टीम अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। प्रथम दृष्टया यह पूरा मामला राइस मिलर्स द्वारा आपस में सांठ गांठ कर सरकार द्वारा खरीदे गए धान का उठाव कर दूसरे राइस मिलर के नाम पर चावल जमाकर उससे पैसा लेने यानी सरकारी चावल को बेचने के साथ साथ परिवहन राशि में चोरी का है।

सहायक खाद्य अधिकारी नटवर राठौर ने कहा जिले का शासकीय धान का चावल जेपी अग्रवाल मिल वाले कोटा के राइस मिल में बेचने के लिए भेज रहे हैं। इस आशंका से कि सरकारी चावल को दूसरे जगह भेजा जा रहा है चावल जब्त कर लिया है। पेंड्रा पुलिस जांच कर रही है।

कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया ने कहा पुलिस ने दो ट्रक भरकर चावल पकड़ाया। ड्राइवर पूछताछ में उसने राइस मिल से चावल लेकर निकलने की बात कही। जिसे कस्टम मिलिंग में जमा करने ले जाया जा रहा था। मामले की जांच जारी है।

हर राइस मिलर को सरकारी धान की मिलिंग करने के बाद सरकार की तरफ से निर्धारित अनुपात में नान और एफसीआई को चावल देना होता है। जिसकी आपूर्ति का अनुपात शासन के मापदंडों और मांग के अनुसार कम ज्यादा होता है। यह पूरा मामला भी इसी से जुड़ा हुआ है। राइस मिलर नागरिक आपूर्ति निगम में चावल की आपूर्ति तो निश्चित समय में कर लेते हैं पर एफसीआई के कठोर मापदंड होने की वजह से एफसीआई का पूरा चावल जमा करने में हमेशा देरी होती है। खाद्य विभाग को यही अंदेशा है कि ट्रांसपोर्टिंग में मिलने वाली राशि की चोरी करने के लिए दोनों राइस मिलों ने आपस में सांठगांठ कर शासन से उठाए गए नए धान की मिलिंग कर फूड कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के गोदाम में जमा करने का यह खेल किया था।

सुकमा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद

सुकमा। कोत्तापल्ली व नागराम के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सुरक्षाबल के जवानों ने 5 से 6 नक्सलियों को गोली लगने का दावा किया है। साथ ही बड़े नक्सली कैंप को ध्वस्त करने का दावा भी जवान कर रहे हैं। आसपास के इलाके में सर्चिंग कर विस्फोटक पदार्थ के साथ ही भारी मात्रा में नक्सली सामग्री भी बरामद किया है। फिलहाल जवानों का सर्चिंग अभियान इलाके में जारी है।

सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने बताया चिंतलनार थाना क्षेत्र के नागराम व कोत्तापल्ली के जंगलों में नागराम एलओएस के नक्सलियों की उपस्थिति की जानकारी मुखबिर से मिली थी। जानकारी मिलते ही नक्सल अभियान के लिए डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, कोबरा 201 बटालियन की संयुक्त टीम को ऑपरेशन के लिए कोत्तापल्ली के जंगलों में रवाना किया गया। जवानों ने नक्सलियों के डेरे पर धावा बोल दिया और दोनों ही ओर से भारी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगलों की आड़ लेकर भाग खड़े हुए। इस मुठभेड़ में जवानों ने 5 से 6 नक्सलियों को गोली लगने का दावा किया है।

बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में चुनाव के बाद नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबल की कार्रवाई लगातार तेज हो चली है। अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बल के जवानों को लगातार सर्चिंग के लिए रवाना किया जा रहा है। साथ ही पुलिस कैंप स्थापित करने के लिए भी नक्सलियों के इलाके को पुलिस अपने कब्जे में लेने की कोशिश में जुटी हुई है।

कोल नगरी चिरमिरी में नहीं रुक रही कोयले की चोरी, एसईसीएल पस्त

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। चिरमिरी नगर पालिका में काले हीरे की बहुतायत है। यहां की कोयला खदानों से लाखों टन कोयला निकाला जाता है।लेकिन एसईसीएल की खदानों पर चोरों और कबाड़ियों की भी नजर है। पहले चिरमिरी क्षेत्र में कई कोयला खदानें थी।लेकिन समय के साथ कोयला खत्म होता गया और खदानें बंद हुईं।मौजूदा समय में कुछ ही कोल माइंस क्षेत्र में संचालित हैं।लेकिन बची हुई कोयला खदानों में चोरों ने अपनी नजरें इनायत की हैं।क्योंकि बंद पड़ी खदानों के साथ ही चालू खदानों से भी बड़ी संख्या में लोहा चोरी करके चोर और कबाड़ी मालामाल हो रहे हैं।पुलिस और एसईसीएल प्रबंधन समय समय पर चोरों के खिलाफ कार्रवाई तो करता है लेकिन ना तो चोरी रुक रही है और ना ही चोर।

विश्वस्त सूत्रों ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि चिरमिरी ओपन कास्ट खदान से लगे मुक्तिधाम के इर्द गिर्द कोयला चोर रात के अंधेरे में सक्रिय होते हैं। इस दौरान चोरी का कोयला मुक्तिधाम के आसपास छिपाया जाता है।इसके बाद सुबह के समय गाड़ियों की मदद से इन्हें लोड करके ठिकाने तक पहुंचा दिया जाता है।इस चोरी की भनक एसईसीएल प्रबंधन को भी नहीं है।लिहाजा चोरी धीरे-धीरे एसईसीएल को चूना लगा रहे हैं।

एसईसीएल क्षेत्र में इस तरह का अवैध कारोबार करना कोई नई बात नहीं है।कई बार कार्रवाई हुई है।लेकिन चोरी नहीं रुकती।इस बारे में एसईसीएल प्रबंधन के उच्च पदाधिकारियों ने कहा कि प्रबंधन के पास पर्याप्त मात्रा में गार्ड नहीं हैं। गार्ड शिफ्ट वाइस काम करते हैं। रात के अंधेरे में चोरों का एक बड़ा समूह देखकर अकेला गार्ड क्या कर सकता है।फिर भी प्रबंधन समय-समय पर सख्ती बरत रहा है।लेकिन हकीकत ये है कि इस सख्ती का चोरों और अवैध कारोबारियों पर कोई असर नहीं पड़ता है।

वहीं इस बारे में बीजेपी नेता प्रदीप सलूजा की माने तो मौजूदा समय में प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है। क्षेत्र में बीजेपी के ही विधायक हैं। उन्होंने यहां के प्रशासनिक अधिकारी सीसी मैडम को बुलाकर साफ शब्दों में कार्रवाई करने को कहा है।प्रशासन को किसी भी तरह का अवैध कारोबार करने से मना किया गया है। वहीं थाना प्रभारी दीपेश सैनी का कहना है कि अभी तक कोयले की चोरी के मामले में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई है। ना ही किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है।

थाना प्रभारी दीपेश सैनी ने कहा हमारी पेट्रोलिंग पार्टी लगातार गश्ती करते रहती है। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होगी उसे पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले जो भी कोयले के तस्करी पर अवैध कारोबार चला है। उस पर पुलिस ने कार्यवाई की है। लेकिन वर्तमान में अभी कोई भी ऐसी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। वहीं कोल तस्करी के मामले में जब एसईसीएल चिरमिरी के मुख्य महाप्रबंधक नवनीत श्रीवास्तव से जानकारी ली गई तो उनका कहना है कि क्षेत्र में किसी भी तरह की कोल तस्करी या कबाड़ बेचे जाने को लेकर शिकायत मिली तो उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी।इसके लिए उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

भले ही अफसर और पुलिस ये कह रहे हो कि क्षेत्र में कोल का अवैध कारोबार नहीं हो रहा है,और यदि हुआ तो कार्रवाई होगी।लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। मीडिया ने जो तस्वीरे इकट्ठा की है उसमें माइंस का कोयला कहीं और दिख रहा है।ऐसे में ये कोयला उस जगह पर कैसे आया ये जांच का विषय है।एसईसीएल प्रबंधन कोयले और कबाड़ की चोरी की शिकायत नहीं करता,क्योंकि बंद पड़ी खदानों में क्या कुछ है और क्या नहीं ये कोई नहीं जानता।लेकिन इतना जरुर है चोरी के इस खेल में पूरा नुकसान आखिरकार एसईसीएल का ही हो रहा है।

खनिज विभाग ने दो कोल डिपो पर की कार्रवाई

लगाया 10 लाख का जुर्माना

बिलासपुर। खनिज विभाग ने दो कोयला डिपो पर कार्रवाई करते हुए 10 लाख की पेनाल्टी लगाई है। खनिज विभाग ने शिकायत के आधार पर मौर्य कोल डिपो में अवैध कोयला-पत्थर का भण्डारण और कोयला चोरी के मामले में 5 लखा 43 हजार 940 रुपये का जुर्माना और पेंड्रीडीह स्थित वेदांता मिनरल्स पर 4 लाख 32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

रतनपुर क्षेत्र के मोहतराई स्थित रोमी मौर्य कोल डिपो चल रहा था। 12 जुलाई 2023 को डिपो का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था, लेकिन संचालक द्वारा डिपो चलाया जा रहा था। ट्रांसपोर्टर पंकज सिंह गांधी ने चिरमिरी के विजय वेस्ट खदान से बी-ग्रेड के जी-5 कोयले की रोमी मौर्य डिपो में चोरी कर मिलावट करने का केस दर्ज कराया था। अवैध डिपो संचालक को खनिज की वैधता प्रमाणित करने नोटिस जारी किया गया था। जिस पर अवैध खनिज मात्रा का प्रतिपरीक्षण के बाद 5,43,940/- जुर्माना लगाया गया है।

इसके अतिरिक्त वेदांता मिनरल्स के संबंध में भी भंडारण नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हुए डिपो संचालक की अनियमित संचालन की शिकायत पर विभाग को मिली थी। इस पर खनिज अमला के द्वारा जांच के बाद 4 लाख 32000 रुपये पेनाल्टी लगाई गई है।

भिलाई में डायरिया से महिला की मौत, मचा हड़कंप

भिलाई। खुर्सीपार के क्षेत्र वार्ड 42 गौतम नगर में फैले डायरिया को जिला व निगम प्रशासन नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है लेकिन स्थिति हाथ से निकलती जा रही है। खुर्सीपार में रहने वाली एक महिला की अस्पताल पहुंचने के पहले ही मौत हो गई। जांच में पता चला है कि वो महिला भी डायरिया पीड़ित थी।

राजीव नगर खुर्सीपार निवासी महिला करमेहता (52) की डायरिया से मौत हो गई। रविवार शाम को महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। जिसके बाद उसका पति संतराम गौतम नगर के स्वास्थ्य शिविर में लेकर गया। जहां से उसे दवाई देकर भेज दिया गया। दवाई से कोई असर नहीं होने पर महिला को उसी रात जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां से उसे रायपुर रेफर कर दिया गया। लेकिन महिला रायपुर न जाकर अपने घर आ गई। हालत ज्यादा खराब होने पर महिला के परिजन उसे शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज लेकर निकले लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

रविवार को गौतम नगर खुर्सीपार में डायरिया के 34 मामले सामने आए थे। सोमवार को 32 व मंगलवार को 20 मरीज मिले हैं। डायरिया फैलने के बाद नगर निगम हरकत में आया है। पूरे क्षेत्र में साफ सफाई कराई जा रही है। नालियों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो रहा है। घरों में क्लोरीन को गोली बांटी जा रही है। पाइप लाइन में आने वाले पानी का सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजा गया है। गौतम नगर में कुछ स्थानों पर नाली के भीतर से गुजरी पाइप लाइन को बदला गया। निगम महापौर नीरज पाल और पार्षद दया सिंह वार्ड में लगातार घूम कर सुधार कार्य का जायजा ले रहे हैं।

डायरिया का मुख्य कारण पानी है। ऐसे में पीने के लिए साफ पानी का ही इस्तेमाल करें। सबसे अच्छा रहेगा यदि उबाल कर पानी पिया जाए। बाहर का खुले में रखा खाना खाने से बचें। डायरिया होने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में ओआरएस का घोल बार बार पीते रहे और तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल जाएं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

पुलिस ने अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर की कार्रवाई

महासमुंद। जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने महासमुंद-राजिम के बीच हथखोज में महानदी से अवैध रेत खनन करते 3 चैन माउंटेन मशीन और लगभग 25 हाइवा को जब्त किया है। इस मामले में पुलिस दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है। वहीं, इस कार्रवाई में खनिज विभाग की टीम नदारत मिली। उल्लेखनीय है कि, जिले में लगातार अवैध रूप से रेत का उत्खनन और परिवहन हो रहा है। इसकी शिकायतें मिलने के बाद अब पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं, खनिज विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसका फायदा लगातार रेत माफिया उठा रहे हैं।

खौलती खीर में छात्र के गिरने पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

बिलासपुर। खौलती खीर में छात्र के गिरने के मामले पर हाईकोर्ट ने स्वत- संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने मीडिया की खबरों पर संज्ञान लेते हुए मामले में बिलासपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर शपथपत्र में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। बता दें, बीते 16 दिसंबर को बिल्हा विकासखंड के शासकीय प्राथमिक स्कूल दोमुहानी में मध्यान्ह भोजन में बच्चों के लिए खीर बनाई गई थी। इस दौरान हेडमास्टर और टीचर बच्चों को भोजन करने के लिए क्लास रूम में बुलाने गए। इसके बाद बच्चे एक साथ मध्यान्ह भोजन लेने के लिए किचन में पहुंचे। इस दौरान खीर की कड़ाही घेर कर बच्चे खड़े हो गए। तभी तीसरी कक्षा का छात्र आदित्य कुमार धीरज उबलती खीर में गिर गया। आनन- फानन में महिलाओं ने उसे उठाया। खीर में गिरने से छात्र का हाथ बुरी तरह से झुलस गया, जिससे वह रोने लगा। कुछ समय बाद छात्र दर्द से तड़पने लगा। शिक्षकों ने जख्मी छात्र को अस्पताल पहुंचाने के बजाय उसे घर भेज दिया।

नक्सल प्रभावित कुधूर में शिक्षा स्वास्थ्य की राह हुई आसान

कोण्डागांव। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की तस्वीर बदल रही है। गांव में विद्युत पहुंचने से आधुनिक सुख-सुविधाओं का ग्रामीण बखूबी इस्तेमाल कर रहे है। इन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सड़क योजना के सड़क नेटवर्क के साथ-साथ बिजली का भी नया नेटवर्क तैयार हो रहा है। कोण्डागांव जिले के पश्चिमी छोर पर अतिसंवेदनशील क्षेत्र में बसे कुधूर गांव में पिछड़ेपन और विकास की रोशनी से अछूता था। अतिसंवेदनशील स्थानों में नक्सल घटनाएं इन इलाकों के विकास में सबसे बड़ी बाधा थी। लेकिन अब यहां की तस्वीर बदलते जा रही है। बिजली और सड़क की सुविधा मिलने से आने से लोगों के लोगों को सामाजिक, आर्थिक विकास की नये रास्ते खुले है। अब यहां प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना से गांव में बिजली की लाइने पहुंची है। गांव के लोग बहुत खुश है कि अब गांव तक आने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा सड़क भी बन गयी है। गांव में अब आटाचक्की, फोटो कापी दुकान जैसी दुकानें भी खुल गयीं हैं।

पूर्व कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल गिरफ्तार

मनेंद्रगढ़। पूर्व विधायक विनय जायसवाल को रेल रोको आंदोलन में शामिल होने के लिए रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय जायसवाल, चिरमिरी महापौर कंचन जायसवाल और कांग्रेस पार्षद रेलवे थाने पहुंचे थे। बता दें कि रेलवे पुलिस ने रेल रोको आंदोलन के दौरान प्रदर्शन को लेकर विनय जायसवाल सहित करीब 25 कांग्रेस के नेताओं को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था। सभी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ रेल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।

धमतरी में नशीली दवाओं का काला कारोबार

धमतरी। शहर में नशीली दवाओं का कारोबार फैलता जा रहा है। जिसकी जद में नाबालिग और युवा आ रहे हैं। धमतरी पुलिस ने नशे के सामान की सप्लाई करने वाले तीन आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों को पास से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाइयां बरामद हुई है। धमतरी शहर के साथ ही जिलेभर में नशीली दवाओं का कारोबार इतना फैला है कि आरोपी 7 रुपये की टैबलेट को 100 से 150 रुपये में बेच रहे हैं। पुलिस को पिछले कई दिनों से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंधित नशीली टेबलेट की अवैध रूप से खरीदी-बिकी की शिकायत मिल रही थी। नशीली दवाओं और इस व्यवसाय से संलिप्त व्यक्तियों पर अंकुश लगाने पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने सख्त निर्देश दिए। जिस पर थाना सिटी कोतवाली और सायबर सेल की संयुक्त टीम आरोपियों की तलाश कर रही थी। धमतरी पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि तीन आदमी विंध्यवासिनी वार्ड में एक हॉटल के पास अवैध रूप से नशीली टेबलेट की बिक्री कर रहे हैं।

राजनांदगांव में 8 लाख से अधिक लोगों का बनाया गया आयुष्मान कार्ड

राजनांदगांव। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाभारत सरकार की योजनाओं से नागरिकों को जागरूक करने एवं शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोबाईल वैन के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब हितग्राही अपना एवं अपने परिवार का आयुष्मान कार्ड मोबाईल एप के माध्यम से स्वयं निःशुल्क बना सकते हैं। इसके लिए राशन कार्ड एवं आधार कार्ड दस्तावेज की आवश्यकता होगी।

आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सर्वप्रथम प्ले स्टोर से आयुष्मान ऐप एवं आधार फेस आईडी एप को डाउनलोड कर लें। इसके बाद आयुष्मान ऐप में लॉगिन पर जायें और बेनिफिसरी विकल्प को चुने। फिर अपना मोबाईल नंबर दर्ज करें एवं ओटीपी डालकर लॉगिन करें। स्टेट छत्तीसगढ़ व स्कीम राशन कार्ड विकल्प का ही चयन करें। सर्च बाय में डिस्ट्रिक में अपना जिला चुने और फैमिली आईडी में राशन कार्ड नंबर दर्ज कर सर्च करें।

परिवार के सदस्यों की जानकारी प्रदर्शित होगी, जिन सदस्यों का नाम हरा रंग में होगा, उनका आयुष्मान कार्ड बन चुका है एवं जिन सदस्यों का नाम नारंगी रंग में होगा उनका कार्ड बनाना होगा। उनके नाम के सामने डू ई-केवाईसी विकल्प प्रदर्शित होगा। डू ई-केवाईसी विकल्प का चयन करें आगे आधार प्रमाणीकरण व सत्यापन हेतु 4 विकल्प आधार ओटीपी, फिंगर प्रिंट, ईरिस स्कैन व फेस एयेंटिफिकेशन प्रदर्शित होंगे। यदि आधार कार्ड से लिंक मोबाईल नंबर उपलब्ध हैं, तो आधार ओटीपी विकल्प का चयन करें और यदि आधार से लिंक मोबाईल नंबर उपलब्ध नहीं हो तो फेस एयेंटिफिकेशन विकल्प का चयन करें। यदि आपके पास फिंगर प्रिंट बायोमेट्रिक डिवाइस उपलब्ध हैं, तो फिंगर प्रिंट विकल्प का चयन कर आधार प्रमाणीकरण पूर्ण कर ले। आधार प्रमाणीकरण के बाद कैप्चर फोटो विकल्प पर जाकर अपना क्लोजअप फोटो कैप्चर करना होगा। इसके पश्चात पता व मोबाईल नंबर की जानकारी भर कर सबमिट बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार सबमिट करते ही आपका केवाईसी पूर्ण हो जाएगा। केवाईसी एयेंटिफिकेशन अप्रूवल हो सकता है। एयेंटिफिकेशन अप्रूवल होने पर कार्ड डाउनलोड करें। एयेंटिफिकेशन अप्रूवल नहीं होने पर अप्रूवल होने की प्रतीक्षा करें। अप्रूवल हो जाने के बाद अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते है। आयुष्मान कार्ड के संबंध में शिकायत एवं सुझाव टोल फ्री नंबर 104, 14555 पर दी जा सकती है। राजनांदगांव के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एके बसोड़ ने बताया कि जिले में अब तक इस योजनांतर्गत 8 लाख 7 हजार 22 नागरिकों का आयुष्मान कार्ड बन गया है।

सीएम साय के गृह जिले में एसडीएम और 18 ठेकेदारों को शो कॉज नोटिस जारी

जशपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले में कलेक्टर एक्शन मोड में हैं। क्ा।श्व विभाग कार्य की प्रगति की जानकारी नहीं देने पर स्छरूको कारण बताओं नोटिस जारी करने की निर्देश दिए हैं। साथ ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी होने पर 18 ठेकेदारों को कारण बताओं नोटिस जारी करने निर्देश दिए हैं। वहीं लंबे समय से कार्य बंद दो ठेकेदारों का कार्य आदेश निरस्त करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर डॉ। रवि मित्तल ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की बैठक लेकर जल जीवन मिशन के समीक्षा कर ग्रामवार कार्य प्रगति की जानकारी ली। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि 10 ग्रामों में जल जीवन मिशन के कार्य शत प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं और 80-90 प्रतिशत कार्य अधिकांश गांव में कार्य प्रगति पर है। कलेक्टर ने शीघ्र पूर्ण करने के

निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिन ठेकेदारों की प्रगति अत्यंत धीमी है और संतोषप्रद नहीं है, इसकी जानकारी ली। साथ ही 18 ठेकेदारों को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए और जिनके लंबे समय से कार्य बंद है जानकारी लेकर दो ठेकेदारों का कार्य आदेश निरस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीओ पत्थलगांव को कार्य की जानकारी नहीं देने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में लोक स्वास्थ्य यंत्र की विभाग के कार्यपालन अभियंता, कुनकुरी, पत्थलगांव , कासाबेल के एसडीओ उपस्थित थे।

पिछड़े वर्ग, महिलाओं और किसानों का कल्याण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता: राज्यपाल

छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान पक्ष-विपक्ष के बीच हुई नोक-झोंक

रायपुर। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य विधानसभा को संबोधित किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों और सिद्धांतों के अनुरूप, राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में सुशासन के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए समर्पित है। नक्सलवाद से प्रभावित निर्वाचन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मतदान ग्रामीण और वन-निवासी समुदायों की अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी सरकार की कल्याण-केंद्रित पहलों में दृढ़ विश्वास बढ़ता रहेगा।

पिछड़ों का उत्थान करना प्राथमिकता

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बीजेपी के चुनावी वादों का उल्लेख किया गया। हरिचंदन ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए आवश्यक उपाय लागू करेगी। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में अभी भी कई लोग हैं जिन्हें सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, युवा, किसान, वन-आश्रित, ग्रामीण समुदाय और पारंपरिक व्यवसायों में लगे व्यक्तियों को अतिरिक्त संवेदनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता है । ये समूह मेरी सरकार के लिए प्राथमिकता बने रहेंगे। इसमें दो साल से लंबित धान खरीद बोनस का भुगतान, कृषि उन्नति योजना, दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना, महतारी वंदन योजना, घर-घर निर्मल जल अभियान और रानी दुर्गावती योजना जैसी किसान कल्याण योजनाएं जैसे मुद्दों पर मूल्यांकन और निर्णय शामिल हैं।

भाजपा के चुनावी वादों का किया उल्लेख

राज्यपाल ने कहा कि इसमें तेंदूपत्ता संग्रहण दर को 5500 रुपये प्रति मानक बोरा तक बढ़ाना, 4500 रुपये तक बोनस, चरण पादुका जैसी सुविधाओं को फिर से शुरू करना और चुनाव घोषणापत्र में शामिल दूसरी घोषणाएं शामिल हैं। नवनिर्वाचित सरकार को महिलाओं और युवाओं से अटूट विश्वास मिला है। इस विश्वास को और मजबूत करने के लिए महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।सरकार एक लाख रिक्त सरकारी पदों को पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया से भरने, पीएससी मामले की जांच, यूपीएससी के समान सभी प्रमुख परीक्षाओं को व्यवस्थित रूप से आयोजित करने और छात्रों के लिए मासिक यात्रा भत्ता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।सरकार एम्स की तर्ज पर प्रत्येक संभाग में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना और आईआईटी की तर्ज पर प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निर्माण के लिए भी प्रतिबद्ध है।

मतदान संपन्न कराने वाले कर्मियों को दी बधाई

राज्यपाल ने नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि मेरा मानना है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सभी सदस्य इस पवित्र सदन की गरिमा को बढ़ाने के लिए सौहार्द और सम्मानजनक रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। राज्य के विकास के रथ को आगे बढ़ाने और लोगों के विश्वास पर खरा उतरने के लिए दोनों पक्षों के लिए सहयोग करना और आदर्श संसदीय परंपराओं को कायम रखना जरूरी है।इस दौरान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने भारत निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और उन हजारों अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी, जिन्होंने राज्य में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

राज्यपाल के अंग्रेजी में दिए अभिभाषण पर भूपेश व लखमा ने जताई आपत्ति

छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शुरू हुई। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने अंग्रेजी में अभिभाषण दिया जिसे लेकर सदन में हंगामा हो गया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री कवासी लखमा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण कम से कम हिंदी में होना था। दूसरी ओर राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त और राष्ट्रगान के बाद सत्ता पक्ष ने भारत माता जय के नारे लगाए, तो विपक्ष ने छत्तीसगढ़ महतारी की जय बोला। इसके बाद जय श्री राम के भी नारे लगे। फिलहाल कुछ देर में मामला शांत हो गया। इसके सदन की कार्यवाही शुरू हुई।

राज्यपाल के अभिभाषण को पूर्व सीएम बघेल ने बताया नीरस

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन के अभिभाषण को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नीरस करार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल ने अंग्रेजी में भाषण दिया। राज्यपाल का भी भाषण आईना होता है, उसमें वह बात नहीं आई जो छत्तीसगढ़ के लिए जरूरी था। राज्य सरकार ने राज्यपाल से नीरस भाषण कराया। उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट प्रस्तुत हुआ। 18 लाख आवास की बात करते हैं, कल्याण उन्नति योजना है, 3100 रुपए के बारे में कहा गया है, बोनस के बारे में कहा गया है, कर्ज माफी के बारे में मुख्यमंत्री अलग कहते हैं, और उनके नेता अलग कहते हैं। अनुपूरक बजट में भी कोई नई चीज नहीं दिखाई दे रही है। भाजपा जिन वादों को लेकर जनता के बीच गई, वह कदम सरकार बनने के बाद दिखाई नहीं दिया। नक्सली घटनाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सल नियंत्रण पर हमारी सरकार ने काम किया। भाजपा सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है। एक भी मतदान केंद्र नहीं था, जिसमें 0त्न मतदान हुआ हो। अधिक मतदान होना इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस सरकार में नक्सली पर लगाम लगा था।

पूर्व मंत्री पटेल ने मुख्यमंत्री को बताया कठपुतली, मूणत ने किया पलटवार

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अभिभाषण पर सदन के बाहर भी पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी तीर चले। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने मुख्यमंत्री साय को जहां कठपुतली करार दे दिया, वहीं भाजपा विधायक राजेश मूणत ने पलटवार करते हुए कहा कि आज पहले दिन ही कांग्रेस फड़फड़ाने लगी है, थोड़ा इंतजार करिए।

पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि सरकार गठन के बाद भी अब तक कोई निर्णय नहीं होने पर तंज कसते हुए कहा कि किसान टकटकी की लगाकर देख रहे हैं। कांग्रेस सरकार बनते ही 2 घंटे के अंदर ही किसानों के लिए फैसला आ गए थे। इस सरकार के 10 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ है।

कठपुतली की तरह काम कर रहे सीएम

पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने मुख्यमंत्री साय को कठपुतली करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री साय सक्षम व्यक्ति है, रायगढ़ का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है, लेकिन वे एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। वे मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रहे हैं। रिमोट कंट्रोल के द्वारा वह काम कर रहे हैं,

उन्हें यह जल्दी छोड़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के लोगों ने छत्तीसगढ़िया के लिए वोटिंग किया है। वह हिम्मत करके अपना फैसला सुनाएंगे तो विपक्ष उनके साथ है। रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है, या हो सकता है नागपुर में हो।

मुख्यमंत्री को कठपुतली कहे जाने पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को सरकार मानकर चल रही है। उनके मंत्री भी अपने आप को मंत्री मान रहे हैं। अभी भी वह होश में नहीं आए हैं कि सरकार चली गई है, भरोसा खत्म हो गया है। समय के साथ-साथ निर्णय होंगे। जो मोदी जी की गारंटी है वह 100त्न पूर्ण करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, हमारे मुखिया स्पष्ट कर चुके हैं। आज पहले दिन ही कांग्रेस फड़फड़ाने लगी है, थोड़ा इंतजार करिए।

नक्सलियों के लगातार हमले पर भाजपा का गंभीर आरोप

संजय श्रीवास्तव ने कहा- कांग्रेस सरकार के जाने की है बौखलाहट

रायपुर। प्रदेश में नक्सली गतिविधियों में आई अचानक तेजी पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि नई सरकार के बनते ही नक्सलियों ने हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस के जाने की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। नक्सलियों को कांग्रेस का सरंक्षण प्राप्त है।

भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कहा बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को घर में घुसकर मारा गया। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई, तब नक्सली कहते पाए गए थे कि हमारी सरकार आ गई। नक्सलवाद से निपटने के लिए बीजेपी ने 15 साल ईमानदारी से काम किए। नक्सल के मामले हम बिलकुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। विपक्ष इस पर राजनीति करने का काम ना करे। कांग्रेस का आचरण इस मामले में ठीक नहीं हैं,

भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने नक्सली घटनाओं को लेकर विपक्ष ने बैठक कर सरकार को घेरने की बनाई गई रणनीति पर कहा कि जैसी तकलीफ कांग्रेस को है, वैसे तकलीफ नक्सलियों को है। नक्सली गतिविधियों का तिरस्कार करना चाहिए, खिलाफत करना चाहिए, जैसे 15 साल नक्सलियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई लड़ी थी, इस बार भी हम इस मुस्तैदी के साथ नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। नक्सलियों को समाप्त करने का हमारा संकल्प है।

पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के रोहिंग्या मुसलमान को लेकर दिए बयान पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि मोहम्मद अकबर को चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक-एक राष्ट्र विरोधी रोहिंग्या इस प्रदेश में पाए जाते हैं, उनको बाहर निकला जाएगा, चाहे वह रायपुर हो चाहे कवर्धा हो पूरे प्रदेश में कही भी हो। दुर्भाग्य रहा कि हम विपक्ष में रहकर आरोप लगाते रहे, लेकिन कांग्रेस कभी रोहिंग्या के खिलाफ में एक्शन में दिखाई नहीं दी, लेकिन बीजेपी बहुत ईमानदारी के साथ ऐसे सामाजिक, राष्ट्रविरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाने को लेकर भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि दुर्भाग्यजनक बात है। देश के सबसे बड़ी जो पंचायत है, वहां पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा जिस तरीके से मर्यादाओं का संविधान को तार-तार किया जा रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है उपराष्ट्रपति जैसे संविधान प्रमुख की मिमिक्री करते हैं, और उनके नेता उसका वीडियो बना रहे हैं। संविधान को, मर्यादाओं को तार-तार करने का काम जो कांग्रेस ने किया है वह देश की जनता देख रही है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मैं राहुल गांधी से कहूंगा कि कपिल शर्मा का जो शो होता है, वहां जाकर मिमिक्री करें। हम उनके लिए शुभकामनाएं देंगे कम से कम जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है। उसकी मर्यादाओं को संरक्षित करने का काम कांग्रेस करें ऐसा मुझे लगता है।

छग में लगे हलाल उत्पादों पर प्रतिबंध हिंदुत्वनिष्ठ संघटनों ने की मांग

रायपुर। अवैध रुप से हलाल प्रमाण पत्र देने के काले धंधे पर उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। वैसा ही प्रतिबंध छत्तीसगढ़ में भी लगाए जाने की मांग पाटेश्वर धामके पंडित पूज्य बालकदास महाराज, नीलकंठ सेवा संस्थान के पंडित निलकंठ त्रिपाठी महाराज मिशन सनातन के संस्थापक मदनमोहन उपाध्याय, राष्ट्रसेविका समिति की प्रांत सहसंयोजिका ज्योति शर्मा, बजरंग दल के अंकित द्विवेदी, हिन्दू जनजागृति समिति छत्तीसगढ़ के समन्वयक हेमंत कानस्कर पत्रकारवार्ता के माध्यम से की। उन्होंने बताया कि हलाल प्रमाण पत्र का उपयोग कई बड़ी नामी कंपनियां करती है, इसमें से हल्दीराम ने अपने वेबसाइट से हलाल प्रमाण पत्र को हटाया दिया है लेकिन इसकी अधिकृत घोषणा नहीं है, जब तक वे इसकी घोषणा नहीं करते है तब तक हिन्दुत्वनिष्ठ संघटन हलाल उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करता रहेगा। इस संबंध में 28 जनवरी 2024 को एक बैठक आयोजित की गई है जिसमें आगे की रणनीति तय किया जाएगा।

बालकदास महाराज ने कहा कि जिस प्रकार से उत्तरप्रदेश सरकार ने हलाल उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की नई सरकार से हिन्दुत्वनिष्ठ संघटन और संत समाज कर रहा है। निलकंठ त्रिपाठी ने कहा कि हलाल उत्पादों से मिलने वाना धन राष्ट्रीय सुरक्षा पर संकट है, इसके बारे में लगातार जागृत किया जा रहा है। जब तक हलाल अर्थव्यवस्था पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगता है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा।

मदनमोहन उपाध्याय ने कहा कि दुग्धजन्य पदार्थ, शक्कर, बेकरी, नमकीन, रेडी टू ईट, खाद्य तेल, औषधियां, वैद्यकीय उपकरण तथा सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित सरकारी नियमों में उत्पादों के आवरण (कवर) पर हलाल सर्टिफाइड चिन्ह अंकित करने पर कानूनी प्रावधान नहीं है। साथ ही औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन कानून, 1940 तथा संबंधित नियमों में हलाल प्रमाण पत्र का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी भी औषधि, वैद्यकीय उपकरण तथा कॉस्मेटिक के आवरण (कवर) पर हलाल प्रमाण पत्र संबंधित कोई भी तथ्य प्रत्यक्ष आ अप्रत्यक्ष रुप से लिखे हो तो वह एक दंडनीय अपराध है।

एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम शर्मा से की मुलाकात

जल्द से जल्द परीक्षा परिणाम जारी करने लगाई गुहार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों ने नई सरकार से गुहार लगाई है। आज रायपुर जशपुर समेत बस्तर संभाग से राजधानी पहुंचे कई अभ्यर्थीयों ने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाक़ात की और जल्द से जल्द परिणाम जारी करने की मांग की।

बता दें कि बीते करीब 5 साल से ये अभ्यर्थी सब इंस्पेक्टर परीक्षा के परिणाम का इंतज़ार कर रहे है, यह मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में अब तक परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने में स्टे नहीं दिया है। राज्य शासन ने 2018 में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की थी। पांच चरणों में आयोजित इस परीक्षा के पहले चरण में दस्तावेज और शारीरिक माप परीक्षण, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा की प्रक्रिया की गई।

भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, लेकिन पिछले तीन माह से इस परीक्षा का परिणाम रोक दिया गया है। यह मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में अब तक परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने में स्टे नहीं दिया है। इसलिए परीक्षा में शामिल लगभग 1378 परीक्षार्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं।

गौरतलब है कि बीजेपी शासनकाल के दौरान 2018 में सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा आयोजित की हुई थी।जिसमें प्रदेशभर से लगभग 1लाख 45 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल हुआ था। इनमें लगभग 1378 अभ्यर्थी साक्षात्कार तक पहुंचे हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के सभी चरण का पालन करते 2021 में इसे संपन्न कर ली गई है। लेकिन अंतिम चयन सूची जारी नहीं की गई है। चयन सूची जारी करने के लिए अभ्यर्थी पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारियों तक कई बार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया है। वहीं प्रदेश में बीजेपी की सत्ता में वापसी के बाद अभ्यर्थियों की एक बार फिर उम्मीद जगी है।

अब 10 बेड के अस्पतालों को भी तत्काल मिलेगा लाइसेंस

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग होम एक्ट में बड़ा बदलाव करते हुए अब 10 बेड वाले नए अस्पतालों को तत्काल लाइसेंस जारी किए जाएंगे। वहीं 30 बेड वाले अस्पतालों का निरीक्षण किया जाएगा। प्रदेश में 2010 व 2013 में नर्सिंग होम एक्ट बनाया गया था और इतने सालों बाद बदलाव पहली बार किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार छोटे अस्पतालों को तत्काल लाइसेंस देने से डॉक्टरों की परेशानी दूर होगी। ऐसे अस्पतालों में मरीजों का तत्काल इलाज होने लगेगा। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के अनुसार तत्काल लाइसेंस जारी करने के पहले अस्पताल प्रबंधन को नर्सिंग होम एक्ट के मापदंडों का पूरा पालन करने संबंधी एफिडेविट देना होगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अफसर अगले एक माह में उस अस्पताल के मापदंडों की जांच करेंगे। 11 से 30 बेड वाले अस्पतालों को लाइसेंस जारी करने के लिए तीन माह के भीतर निरीक्षण करना होगा। 30 बेड वाले अस्पतालों को स्वतः लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अफसर निरीक्षण कर जरूरी मापदंडों की जांच करेंगे।

कांग्रेस ने प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला को जारी किया कारण बताओ नोटिस

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में हार के बाद पीसीसी (प्रदेश कांग्रेस कमेटी) में बगावत के सुर उठने लगे है, जिसके बाद पार्टी के खिलाफ बयान बाजी करने वालों पर पार्टी ने एक्शन लिया है। नेता हो या पूर्व विधयक पार्टी के खिलाफ बयान बाजी करने वालों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। इसी कड़ी में आज पीसीसी ने प्रदेश कांग्रेस महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस कमेटी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखकर अपना दुख और गुस्सा जाहिर किया था। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि, नेता प्रतिपक्ष चयन की औपचारिकता भी पूरी कर ली गई। दिल्ली के नेताओं के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन का

हब और मौज मस्ती का केंद्र बन गया है। चंद्रशेखर शुक्ला ने पत्र में लिखा कि 'जो हार के कारणों के लिए जिम्मेदार था उन्हीं के साथ चुपचाप मीटिंग कर ली गई। नेता प्रतिपक्ष चयन की औपचारिकता भी पूरी कर ली गई। दिल्ली के नेताओं के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन का हब और मौज मस्ती का केंद्र बन गया है। एक एक प्रकोष्ठ में चार चार अध्यक्ष बनाए गए हैं। पैसे लेकर नियुक्तियां की गई है। जोगी कांग्रेस के लोगों को उपकृत किया गया'। इतना ही नहीं उन्होंने भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं पर भी सवाल खड़े किए।

चंद्रशेखर शुक्ला ने पत्र में सवाल करते हुए लिखा था कि हमारी योजनाएं और प्लानिंग क्यों धाराशाही हुई? हमारे सर्वे जो 7-7 बार हुआ, वह क्यों असफल हुआ? नेताओं को क्षेत्र बदलकर, (महंत राम सुन्दर दास जी एवं छाया वर्मा जी) क्यों चुनाव लड़वाया गया? ब्लॉक एवं जिला कांग्रेस कमेटी से आए नामों पर, क्यों नहीं टिकिट बांटा गया? दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि दिल्ली के नेताओं का छत्तीसगढ़ राजनीतिक पर्यटन हब, मौज-मस्ती का केन्द्र बन गया है। एक-एक प्रकोष्ठ में 4-4 प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। एलडीएम रूपी के तमाशा किया गया। पैसे लेकर नियुक्तियां की गईं। जिस जोगी कांग्रेस को बामुश्किल हमनें संघर्ष कर बाहर किया था, उन्हें बुला-बुलाकर उपकृत कर, राजनीतिक और शासकीय पदों से सम्मानित किया गया।

डोंगरगढ़ में कांग्रेस शहर अध्यक्ष गोमास्ता ने दिया इस्तीफा

राजनांदगांव। विधानसभा चुनाव के दौरान डोंगरगढ़ शहर में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त से दुखी शहर अध्यक्ष संजीव गोमास्ता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को अपना त्यागपत्र भेज दिया है।

त्यागपत्र में उन्होंने नैतिकता के आधार पर डोंगरगढ़ शहर अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का जिक्र किया है। अलबत्ता उन्होंने यह जरूर उल्लेख किया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान शहर अध्यक्ष होने के बावजूद उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। पिछले 5 वर्ष से संगठन में वह उपेक्षित और अपमानित महसूस करते रहे। उन्होंने यह भी लिखा है कि ब्लॉक अध्यक्ष रहते हुए प्रदेश कांग्रेस से घोषित सूची में पार्षद टिकट प्राप्त होने के बाद नामांकन के पश्चात अचानक उनकी टिकट काट दी गई। उन्होंने यह भी लिखा है कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में डोंगरगढ़ शहर के पदाधिकारियों की पूर्ण उपेक्षा होती रही। इसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी हर्षिता स्वामी बघेल के लिए निष्ठापूर्वक काम किया। डोंगरगढ़ शहर में भाजपा को बढ़त मिली। शहर में कांग्रेस को मिली हार की वजह से उन्होंने त्यागपत्र दिया है। गोमास्ता 2014 से 8 वर्षों तक डोंगरगढ़ शहर अध्यक्ष के पद पर रहे। उन्होंने अपने इस्तीफे की अन्य वजह का भी जिक्र किया है।

उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर विपक्ष ने भारतीयों का दिल दुखाया

नीरज कुमार दुबे

भारत की संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और हमारे देश के सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक भी है। संसद भवन कोई इमारत मात्र नहीं बल्कि करोड़ों देशवासियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला पवित्र स्थल भी है। संसद से हर भारतीय गहरा भावनात्मक लगाव रखता है लेकिन जिस तरह से संसद के कुछ सदस्य ही संसद की मर्यादा और सम्मान को ठेस पहुँचा रहे हैं वह सचमुच आहत करने वाला है। देखा जाये तो विपक्ष के बड़े नेता विदेशी धरती पर जाकर तो भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाते ही हैं अब उन्होंने देश में भी संसदीय लोकतंत्र का उपहास उड़ाना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि अमर्यादित आचरण के चलते सदन से निलंबित किये गये विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को संसद को ''संविधान की कब्रगाह'' बताते हुए इसकी तुलना उत्तर कोरियाई सदन से कर हर भारतीय का दिल दुखाया है। शिरोमणि अकाली दल की नेता और सांसद हरसिमरत कौर बादल को संसद संविधान की कब्रगाह नजर आई तो दूसरी ओर तमाम तरह के आर्थिक अपराधों के आरोपों से घिरे कांग्रेस नेता और सांसद कार्ति चिदंबरम ने दावा कर दिया है कि संसद जल्द ही उत्तर कोरियाई सदन की तरह हो जाएगी। कार्ति चिदंबरम ने कहा है कि हम उत्तर कोरियाई सदन की तरह बनने वाले हैं और केवल एक चीज की कमी है कि जब प्रधानमंत्री सदन के अंदर आएं तो सब साथ मिलकर तालियां बजाएं। कार्ति चिदंबरम ने कहा कि यह एक सांकेतिक सदन बनने वाला है। बात सिर्फ लोकतंत्र के अपमान की भी नहीं है। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जिस तरह मिमिक्री कर उनका अपमान करने की होड़ चल पड़ी है और हमारे संवैधानिक संस्थानों पर राजनीतिक हमले किये जाने का जो सिलसिला चला है वह एक तरह से भारत की छवि पर हमला है। कभी प्रधानमंत्री के लिए तानाशाह, हिटलर, नीच या कोई अन्य अपमानजनक शब्द उपयोग किया जाता है तो कभी देश की राष्ट्रपति का अपमान कर दिया जाता है। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जिस तरह अपमान किया गया उसने सार्वजनिक जीवन में मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। यहां यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि राष्ट्रपति द्रौपद्री मुर्मू हों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों...यह सभी साधारण और गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इन सभी को राजनीति विरासत में नहीं मिली बल्कि यह जीवन में अभाव और संघर्षों पर विजय हासिल करते हुए यहां तक पहुँचे हैं लेकिन लगता है कि दिल्ली पर दशकों तक राज करने वाले राज परिवार के लोगों को यह सब भा नहीं रहा इसलिए सुनियोजित तरीके से शीर्ष पदों पर बैठे लोगों पर हमले किये और करवाये जा रहे हैं। विपक्ष ने ऐसा ही रवैया न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थानों के प्रति भी अपनाया हुआ है। कोई फैसला अपने मन मुताबिक नहीं आये तो न्यायपालिका पर सवाल उठा देना, चुनाव हार गये तो ईवीएम पर सवाल उठा देना, नोटिस मिल जाये तो आयकर विभाग या ईडी पर सवाल उठा देना और पूछताछ के लिए बुला लिया जाये तो सीबीआई पर राजनीतिक हमला कर देना अब विपक्षी नेताओं की आदत में शुमार हो चुका है। लेकिन यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है और जनता की अदालत हर चुनाव में त्वरित न्याय करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति से सहानुभूति जताते हुए जो कुछ कहा है वह मात्र उनके समर्थन में खड़ा होना नहीं है बल्कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के शब्दों से उनके मन की पीड़ा और चिंता की भी झलक मिलती है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि संसद परिसर में उपराष्ट्रपति को जिस तरह अपमानित किया गया, उससे वह बेहद व्यथित हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन उनकी अभिव्यक्ति शालीन तथा मर्यादा के दायरे में होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमारी संसदीय परंपराएं हैं जिन पर हमें गर्व है और हम उन्हें बरकरार रखने की आशा करते हैं।

कांग्रेस और इंडिया सबक लेने को तैयार नहीं

अजय सेतिया

पांच विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद हुए एक ओपिनियन पोल के नतीजे चौंकाने वाले हैं। इस ओपिनियन पोल में कहा गया है कि लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी, और कांग्रेस अपनी मौजूदा सीटों पर ही बनी रह सकती है, या ज्यादा से ज्यादा 20 सीटें बढ़ेंगी। यह ओपिनियन पोल इंडी एलायंस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इंडी एलायंस के सारे घटक दल 100 से 125 तक सीटों में निपट रहे हैं। विधानसभा चुनावों से पहले इसी एजेंसी के ओपिनियन पोल में भाजपा की सीटें ज्यादा से ज्यादा 296 तक और एनडीए की सीटें 326 तक बताई गई थीं, और इंडी एलायंस की सीटें 190 तक बताई गई थीं। इसका मतलब यह है कि तृणमूल कांग्रेस-ममता, द्रमुक-स्टालिन, शिवसेना-उद्धव, एनसीपी-शरद, जेडीयू-नीतीश, राजद-लालू, सपा-अखिलेश आदि के लिए खतरे की घंटी है। आज चुनाव होते हैं तो इन सभी दलों की सीटें घटेंगी। विधानसभा चुनावों से पहले जो लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कि भाजपा के सामने एक उम्मीदवार खड़ा होने से भाजपा की हार निश्चित है, उन्होंने अब उस तरह की भविष्यवाणियां करना फिलहाल बंद कर दिया है। भाजपा तो इन चुनावों को सेमीफाइनल मानती ही नहीं थी, इंडी एलायंस ही इन चुनावों को सेमीफाइनल बता रहा था। नतीजों के बाद इंडी एलायंस के नेता भी मानने लगे हैं कि इन चुनाव नतीजों से भाजपा को बूस्ट मिला है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम तक ने कहा है कि हिन्दी हार्टलैंड के तीनों राज्यों में कांग्रेस की इतनी करारी हार की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस जमीनी हकीकत को समझ ही नहीं रही थी। इन नतीजों से निराश पी. चिदंबरम यथार्थवादी हो कर कह रहे हैं कि भाजपा के सामने एक उम्मीदवार खड़ा करने पर भी 2024 में उसे नहीं हराया जा सकता। ओपिनियन पोल को हमेशा नकारने वाले पी.चिदंबरम ने अब माना है कि हवा भाजपा के पक्ष में बह रही है। आखिर क्या कारण है कि चुनावों से सिर्फ चार महीने पहले हवा सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में बह रही है। विपक्ष को अपनी चुनावी रणनीति बनाने से पहले उन पहलूओं पर सोचना चाहिए। पी. चिदंबरम ने उन तीन कारणों की तरफ इशारा किया है, जिनके कारण हवा भाजपा की तरफ बह रही है। सबसे पहला विषय है भाजपा का

अति राष्ट्रवाद, दूसरा है भाजपा का चुनावों को गंभीरता से लड़ना और तीसरा है भाजपा की ध्रुवीकरण की राजनीति।

भले ही पी. चिदंबरम ने अति राष्ट्रवाद को नकारात्मक रूप से चिन्हित किया है, लेकिन देश इसे भाजपा के सकारात्मक पक्ष के रूप में देखता है। अति राष्ट्रवाद की आलोचना कांग्रेस को बड़ी महंगी पड़ेगी, लेकिन कांग्रेस के ज्यादातर नेता वामपंथियों और कट्टरवादी मुसलमानों से प्रभावित हो कर राष्ट्रवाद को एक बुराई के रूप में देखते हैं। वामपंथी और देवबंदी राष्ट्रवाद की अवधारणा के ही खिलाफ है, इन दोनों वर्गों की आस्था का केंद्र देश से बाहर है। इसलिए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को राष्ट्रवाद पर आत्ममंथन करना पड़ेगा। सुप्रीमकोर्ट ने रामजन्मभूमि के पक्ष में फैसला देते हुए मस्जिद बनाने के लिए सरकार को पांच एकड़ जमीन देने का आदेश भी सुनाया था। सरकार ने जमीन अलॉट भी कर दी थी, अब जब मस्जिद निर्माण के लिए नींव पत्थर रखने की बात चल रही है, तो (वहाबिज्म में विश्वास रखने वाले) देवबंदी मुस्लिमों के प्रभाव वाले सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मक्का मज्जिद के इमाम (मक्का पर वहाबियों का नियन्त्रण है) से नींव पत्थर रखवाना तय किया है। उन्होंने किसी भारतीय इमाम को नींव पत्थर रखने लिए उपर्युक्त नहीं माना। जबकि बरेलवी मुस्लिम मक्का के इमाम से नींव पत्थर रखवाने के खिलाफ हैं। बरेलवी मुसलमान राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं, इसलिए उनका कहना है कि जिस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामजन्मभूमि मन्दिर का नींव पत्थर रखा है, उसी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही मस्जिद की नींव का पत्थर रखवाया जाना चाहिए। तो यह कहना भी गलत होगा कि भारत के सारे मुसलमान राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं रखते, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों की आस्था देवबंदी विचारधारा में है।

कांग्रेस ने भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रवाद की धारा में लाने की बजाए, खुद ही अपनी धारा बदल ली। आज़ादी के बाद राष्ट्रवाद ही कांग्रेस की सबसे बड़ी पूंजी थी, लेकिन भाजपा ने कांग्रेस की इसी पूंजी को उससे छीन लिया है। जैसे राष्ट्रवाद के कारण कांग्रेस की जड़ें जमी हुई थीं, वैसे ही भाजपा की जड़ें जम गई हैं। इसलिए चिदंबरम ने तो मान लिया है कि 2024 में विपक्ष मोदी को नहीं हरा सकता। क्योंकि भाजपा चुनाव को आख़िरी चुनाव समझ कर लडती है, और कांग्रेस चुनाव को गंभीरता से लड़ ही नहीं पाती। छोटी छोटी घटनाएं कभी कभी चुनाव की दिशा और दशा बदल देती हैं। राहुल गांधी ने राजस्थान के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कह दिया था। मोदी क्रिकेट का मैच राष्ट्रवाद का प्रदर्शन करने के लिए देखने गए थे, भारत हार गया, तो राहुल गांधी ने मोदी को ही पनौती कह दिया। राहुल गांधी चुनाव को गंभीरता से लड़ रहे होते, तो पनौती वाली टिप्पणी करने से पहले सोचते कि लोग इसका क्या अर्थ निकालेंगे।

मोदी देश की जनता के साथ जुड़ चुके हैं, जनता के दिमाग से मोदी को निकालने के लिए कांग्रेस को नकारात्मक राजनीति छोड़ कर सकारात्मक राजनीति करनी होगी। लेकिन हैरानी यह है कि कांग्रेस देश के मिजाज को समझ ही नहीं रही है। देश का मिजाज 370 के खिलाफ था, कांग्रेस ने उसे नहीं पहचाना, बल्कि उसे हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट तक लड़ने वालों का साथ दिया। चिदंबरम जैसे नेता अभी भी भाजपा के राष्ट्रवाद को कांग्रेस की समस्या के रूप में देख रहे हैं। हिन्दू मुस्लिम ध्रुवीकरण का मुद्दा भी इसी से जुड़ा है, वह इससे अलग नहीं है। ध्रुवीकरण के लिए भाजपा जिम्मेदार नहीं है, जैसे कांग्रेस ने राष्ट्रवाद छोड़कर भाजपा को थमा दिया, उसी तरह ध्रुवीकरण का मुद्दा भी कांग्रेस ने खुद भाजपा को थमाया है। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण न करती तो भारत का हिन्दू उसी तरह कांग्रेस को वोट करता रहता, जैसे 1952 से लेकर 1984 तक कर रहा था। देश के हिन्दुओं ने 2004 में एक बार फिर मौक़ा दिया था, लेकिन उस मौके को भी कांग्रेस ने तुष्टिकरण से गंवा दिया। 2014 का चुनाव हारने के बाद ए.के. एंटनी अपनी रिपोर्ट में कांग्रेस की हार के कारणों में सबसे बड़ा कारण मुस्लिम तुष्टिकरण को बता चुके हैं। इसलिए चिदंबरम का यह कहना कि कांग्रेस और विपक्षी दलों को भाजपा के ध्रुवीकरण की काट ढूंढनी होगी, सच्चाई को नकारने का एक ओर प्रयास है। ध्रुवीकरण का हल कांग्रेस के पास ही है, 2018 के गुजरात विधानसभा चुनाव में जब राहुल गांधी ने मुस्लिम तुष्टिकरण छोड़ने के संकेत दिए थे, तो हिन्दुओं ने भी उन्हें बेहतर सीटें देकर फिर से गले लगाने के संकेत दे दिए थे। लेकिन कांग्रेस खुद सबक लेने को तैयार नहीं।

पी. चिदंबरम चौथा कारण भी गिना देते तो अच्छा रहता कि विपक्ष अपनी स्तरहीन राजनीति के कारण जनता में विश्वास खोता जा रहा है। उन्होंने भाजपा की जीत के कारण तो गिना दिए, लेकिन विपक्ष खासकर कांग्रेस की हार के कारण नहीं गिनाए। वह कारण है विपक्षी दलों के नेताओं का संसद के भीतर स्तरहीन व्यवहार। ऐसा व्यवहार जो राजनीत के अनाड़ी ही कर सकते हैं। जिन्हें समाज में बन रही अपनी छवि की चिंता नहीं होती। 13 दिसंबर को लोकसभा में दहशत पैदा करने की जो घटना हुई, विपक्ष उस पर भी परिपक्वता और गंभीरता नहीं दिखा सका। पहले भी एक दर्जन बार से ज्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। खुद कांग्रेस के शासनकाल में ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन न पहले कभी इसे राजनीति का विषय बनाया गया था, न अब बनाया जाना चाहिए था।

विपक्ष ने विधानसभा चुनाव नतीजों से भी कोई सबक नहीं सीखा कि जनता में उसकी कैसी छवि बन रही है। पिछले छह दिनों से दोनों सदनों में इस मांग के लिए हंगामा हो रहा है कि गृहमंत्री आकर बयान दें। सरकार भी अड़ी हुई है कि संसद भवन परिसर गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता, पहले भी कभी गृहमंत्री ने बयान नहीं दिया। दोनों तरफ से अड़ियल रवैये के कारण संसदीय इतिहास में पहली बार 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। दोनों तरफ से अड़ियल होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीच का रास्ता निकालने के बजाए यहाँ तक कह दिया है कि कुछ महीनों में देश की जनता निलंबित सांसदों की सीटें भाजपा सांसदों से भर देगी। उधर सारी मर्यादाओं को लांघ कर विपक्ष के सांसद देश के उपराष्ट्रपति की शर्मनाक मिमिक्री करने की हरकत कर रहे हैं। जिससे जनता के बीच विपक्ष की छवि और खराब होती जा रही है। ऐसी छवि के रहते भाजपा के सामने एक उम्मीदवार खड़ा करने से भी विपक्ष को कोई फायदा नहीं होगा।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

योगचूडामण्युपनिषद् (भाग-17)

गतांक से आगे...

पवित्र या अपवित्र किसी भी अवस्था में ओंकार का जप करने वाला पाप-पंक में नहीं फँसता, संसार में वह जल से अलित पद्मपत्र की तरह निर्लिप्त बना रहता है। जब तक वायु चलती रहेगी, तब तक बिन्दु भी चलायमान होगा, वायु के स्थिर हो जाने पर योगी स्थिरता (निश्चलता) को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वायु की स्थिरता (प्राणायाम) का अभ्यास करना चाहिए।

शरीर में जब तक वायु विद्यमान है, तब तक शरीर में जीव स्थिर रहेगा। शरीर से वायु निकल जाना ही मृत्यु है, इस कारण वायु का निरोध (प्राणायाम) करना चाहिए। जीव शरीर से तब तक नहीं निकल सकता, जब तक शरीर में वायु आबद्ध (स्थित) है, जो व्यक्ति दोनों भृकुटियों के बीच में दृष्टि को स्थिर रखता है, वह काल को जीत लेता है, उसे काल का भय कैसा?

ब्रह्मा भी अल्प काल के भय से (अल्पायु से) मुक्ति पाने के लिए प्राणायाम करते हैं। इसलिए प्राण का निरोध करने के लिए योगियों और मुनियों को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए।

यह प्राण हंस रूप है, जो श्वास के माध्यम से छब्बीस अंगुल बाहर आता है। प्राणायाम नासिका के दोनों छिद्रों अर्थात् बायें दायें मार्ग से करना चाहिए। सभी प्रकार के मलों से नाड़ी चक्र के शुद्ध हो जाने पर योगी प्राणों का निरोध करने (प्राणायाम-सिद्ध होने) में समर्थ हो जाता है। योग का अभ्यास करने के लिए बद्ध पद्मासन लगाकर चन्द्र नाड़ी (बायें स्वर) के द्वारा वायु को भीतर खींचे पूरक करे, पुनः कुछ समय भीतर रोके कुम्भक करे, फिर सूर्य नाड़ी (दायें स्वर) के द्वारा रेचन करे अर्थात् बाहर निकाले। प्राणायाम के समय अमृत समुद्र से निकले हुए गो दुग्ध के समान श्वेत वर्ण के चन्द्रबिम्ब का ध्यान करने से साधक सुखी होता है।

क्रमशः ...

पंडित सुंदरलाल शर्मा

प्रदीप सिंह

जिस प्रकार भारत में राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत राजा राममोहन राय को माना जाता है, उसी तरह छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के प्रणेता पं. सुन्दरलाल शर्मा को माना जाता है। उन्होंने ही इस क्षेत्र में सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात किया था । बहुमुखी प्रतिभा के धनी पं. सुन्दरलाल शर्मा की ख्याति छत्तीसगढ़ में एक महान साहित्यकार, मूर्तिकार, चित्रकार, शिक्षाविद, समाज सुधारक, संघर्षशील नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी के रूप में है।

छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में विख्यात पं. सुन्दरलाल शर्मा का जन्म 21 दिसम्बर, 1881 को राजिम के पास महानदी के तटवर्ती ग्राम चमसुर (चंद्रसूर) में हुआ था। उनके पिता पं.

जियालाल तिवारी कांकेर रियासत में विधि सलाहकार थे। किशोरावस्था में ही सुन्दरलाल शर्मा ने कविताएँ, लेख एवं नाटक लिखना प्रारंभ कर दिया था। वे आशु कवि थे। नाट्यलेखन तथा रंगमंच में उनकी गहरी रुचि थी। सन् 1898 में उन्होंने पं. विश्वनाथ दुबे के सहयोग से राजिम में कवि समाज की स्थापना की। यह ऐसी पहली साहित्यिक संस्था थी जिसने छत्तीसगढ़ अंचल में साहित्यिक चेतना जागृत की।

सुन्दरलाल के हृदय में बाल्यावस्था से ही हिंसा के प्रति घृणा का भाव था। जीव हत्या कर मांसाहार को देख उन्होंने बाल सुलभ हठ से अनशन शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप स्वजनों द्वारा उसी दिन से मांसाहार का परित्याग कर दिया गया। इस प्रकार उनके परिवार में सदियों से चली आ रही एक कुप्रथा का अंत हो गया।

पं. सुन्दरलाल सन् 1903 में अखिल भारतीय कांग्रेस के सदस्य बने। उन्होंने 1907 में सूरत में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में जाने वाले छत्तीसगढ़ के युवाओं का नेतृत्व किया। सूरत से लौटते ही उन्होंने नारायण राव मेघावाले तथा अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार-प्रसार का आंदोलन शुरू किया। उनका मानना था कि जब तक भारत के लोग स्वदेश में बनी वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे तब तक न तो गाँवों की गरीबी मिटेगी और न ही राष्ट्रीय भावनाओं का जागरण होगा। इस हेतु उन्होंने अपनी जमीन जायदाद बेचकर राजिम, धमतरी और रायपुर में स्वदेशी वस्तुओं की कई दुकानें खोलीं तथा लगातार घाटा होने पर भी उन्हें वर्षों चलाया। गाँवों से अज्ञानता, अंधविश्वास तथा कुरीतियों को मिटाने के लिए वे शिक्षा के प्रचार-प्रसार को आवश्यक समझते थे। इस हेतु उन्होंने 1907 में राजिम में संस्कृत पाठशाला तथा कुछ वर्षों बाद एक वाचनालय स्थापित किया। रायपुर के बाहमणपारा में बाल समाज पुस्तकालय की स्थापना का श्रेय भी उन्हें ही है। पं. सुन्दरलाल शर्मा ऐसे प्रथम विचारक थे जिनकी स्पष्ट मान्यता थी कि दलितों के भी समाज में सवर्णों की भाँति राजनैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक अधिकार हैं। वे दलितों को समाज में बराबरी का दर्जा प्रदान करने के लिए सतत् संघर्षशील थे।

भारत-अमेरिका के बीच रिश्तों की समीक्षा करने का वक्त

नीरज मनजीत

क्या भारत और अमेरिका के दोस्ताना रिश्ते मुश्क़िल दौर से गुज़र रहे हैं? वैश्विक कूटनीति के ताक़तवर हलकों में यह सवाल शिद्दत से पूछा जा रहा है। हालाँकि दोनों देशों के प्रवक्ताओं की ओर से यह ज़ाहिर किया जा रहा है कि मसला कुछ भी नहीं है, सब कुछ मीठा-मीठा ही है। मगर बारीक़ी से गौर करें तो रिश्तों में कुछ ख़राश नज़र आ जाती है। मसला नवंबर माह में शुरू हुआ, जब अमेरिकी प्रशासन के न्याय विभाग ने यह गंभीर आरोप लगाया कि भारत सरकार का कोई ख़ुफ़िया अधिकारी अमेरिका के एक वकील गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साज़िश रच रहा है। इसके पहले अमेरिका के एक अखबार फाइनैंशियल टाइम्स ने भी इस बात का खुलासा किया था। इस ख़ुफ़िया अधिकारी का नाम नहीं बताया गया है। इल्ज़ाम लगाया गया कि इस अधिकारी ने निखिल गुप्ता नाम के एक ड्रग पैडलर को पन्नू को जान से मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। निखिल गुप्ता ने इस काम की सुपारी अमेरिका के एक शख़्स को सौंप दी। बाद में पता चला कि वह शख़्स सीआईए का एक एजेंट है। दरअसल सीआईए को पन्नू की हत्या की साज़िश की भनक लग गई थी, इसलिए उन्होंने अपने एक एजेंट को निखिल के पीछे लगा दिया और वह सीआईए के जाल में फँस गया।

अमेरिका के कहने पर निखिल को चेकोस्लोवाकिया में गिरफ़्तार किया गया और प्राग की जेल में डाल दिया गया। अमेरिकी अधिकारी फ़िलहाल निखिल का प्रत्यर्पण करवा कर अमेरिका लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उससे पूछताछ कर मामले को उजागर किया जा सके। इधर निखिल के रिश्तेदारों ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में वाद दाख़िल करके उसे बेगुनाह बताया है और उसे चेकोस्लोवाकिया सरकार से अपील कर भारत लाने की मांग की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूँकि उसे चेकोस्लोवाकिया के कानूनों के तहत

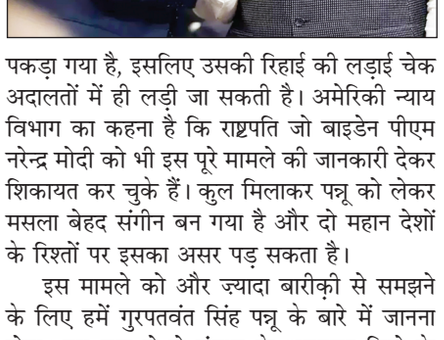

पकड़ा गया है, इसलिए उसकी रिहाई की लड़ाई चेक अदालतों में ही लड़ी जा सकती है। अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम नरेन्द्र मोदी को भी इस पूरे मामले की जानकारी देकर शिकायत कर चुके हैं। कुल मिलाकर पन्नू को लेकर मसला बेहद संगीन बन गया है और दो महान देशों के रिश्तों पर इसका असर पड़ सकता है।

इस मामले को और ज़्यादा बारीक़ी से समझने के लिए हमें गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में जानना होगा। पन्नू मूल से से पंजाब के अमृतसर जिले के खनवाला गाँव का रहने वाला है। नब्बे के दशक में उसने पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली और अमेरिका चला गया। वहाँ उसने अमेरिका की नागरिकता लेकर फाइनेंस में एमबीए किया और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से दोबारा वकालत की डिग्री लेकर प्रैक्टिस शुरू कर दी। 2007 में उसने एक अलगाववादी संगठन सिख फ़ॉर जस्टिस की स्थापना की और पंजाब के अलगाववादी लोगों को पृथक खालिस्तान की माँग करने के लिए भड़काने लगा। 2020 में भारत सरकार ने उसे भगोड़ा आतंकवादी घोषित कर दिया। फ़िलहाल उसके ख़िलाफ़ राजद्रोह के तीन मामलों सहित 22 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। आए दिनों वह भड़काऊ बयान देकर सिखों को उकसाता रहता है। कुछ दिनों पहले उसने 13 दिसंबर को भारतीय संसद पर हमला करने की धमकी दी थी। इससे पहले वह 19 नवंबर को वर्ल्डकप फाइनल के दौरान स्टेडियम में भी गड़बड़ी फैलाने की धमकी दी थी। किसान आंदोलन के दौरान उपद्रवियों ने लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराया था, उसमें भी पन्नू का हाथ था। बताया जाता है कि भारत में गड़बड़ी फैलाने के लिए पन्नू को पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई से फंडिंग की जा रही है।

इस पूरे एपिसोड को समझने के बाद सवाल यह पैदा होता है कि भारत से रिश्ते बिगाड़ने की हद तक जाकर अमेरिका एक अलगाववादी आतंकवादी शख़्स से जुड़े मामले को इतना तूल क्यों दे रहा है? वैसे भारत ने एक जाँच एजेंसी गठित करके अमेरिका को भरोसे में लिया है। अमेरिका ने भी इस क़दम का स्वागत किया है, मगर यह मसला इतने भर से ख़त्म नहीं हो जाता। वैश्विक बिरादरी में जो संशय के बादल मँडराने लगे हैं, उन्हें छंटने में काफी वक़्त लगेगा। भारत और अमेरिका के बीच के मीठे रिश्ते दोनों देशों के लिए इस सदी की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसकी शुरुआत पिछली सदी के आख़िरी दशक में नरसिम्हाराव के कार्यकाल में ही शुरू हो गई थी। अटलबिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने इसे आगे बढ़ाया और पीएम नरेन्द्र मोदी ने तो इन रिश्तों को शिखर पर बिठा दिया। दोनों देशों के अंदर में महान लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभिमान और दर्प होना नितांत स्वाभाविक बात है। यह दर्प और स्वाभिमान कहीं अहंकार के दायरे में जाकर एक-दूसरे से टकराने न लगे, संजीदगी से इसका ख़्याल रखना दोनों देशों की जिम्मेदारी है। लगता है फ़िलहाल ये रिश्ते जिस विलोम ठहराव पर हैं, उसकी वजह यही मसला है।

रिश्तों की पार्टनरशिप में अमेरिका को संभवत: भारत से कुछ ज़्यादा अपेक्षाएँ हैं। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक कूटनीति के इलाके में भारत के कुछ क़दमों से इन अपेक्षाओं को कुछ धक्का लगा है। ख़ासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब अमेरिका और नाटो देशों ने रूस के ख़िलाफ़ कई प्रतिबंध लगा दिए थे। ये सारे देश चाहते थे कि रूस के विरुद्ध उठाए गए क़दमों का भारत समर्थन करे, मगर भारत ने अपनी तटस्थता की नीति के तहत ऐसा नहीं किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दो बार रूस के ख़िलाफ़ निंदा प्रस्ताव लाया गया। इसमें सौ से ज़्यादा देशों ने अमेरिका और नाटो देशों के पक्ष में वोट दिया। भारत ने इसमें वोटिंग नहीं की। यह बात भी संभवत: अमेरिकी प्रशासन के कुछ लोगों को नागवार गुजरी है। दूसरी वजह है रूस पर जब कड़ी आर्थिक बंदिशें लगाई गईं, तो भारत ने रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदना जारी रखा और उसे अपनी रेफाइनरियों में शोधित करके कुछ यूरोपीय देशों को बेचकर मुनाफ़ा भी कमाया। अमेरिकी प्रशासन चाहता था कि भारत नाटो प्लस में शामिल हो जाए, पर भारत ने यह प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। कहीं न कहीं ये सारी बातें अमेरिकी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं थीं।

हम यह नहीं मान रहे हैं कि पन्नू मामले को उछालकर अमेरिका भारत पर दबाव डालकर अपनी तरफ़ और ज़्यादा खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतना जरूर कहना होगा कि अमेरिका और भारत मिलकर अपने रिश्तों की पुनर्समीक्षा करें और कहीं गड़बड़ है तो संजीदगी से उसे दूर करें। भारत को पूरी गंभीरता से अमेरिका की वाजिब इच्छाओं की क़द्र करते हुए यह देखना होगा कि कहीं दो महान लोकतांत्रिक देशों का अहम एक दूसरे से टकराने न लगे। अमेरिका को भी भारत की निरपेक्ष आध्यात्मिक दृष्टि का सम्मान करना चाहिए और ग़ैरवाजिब दबाव बनाने के बजाए भारतीय राजनयिकों से स्पष्ट बातचीत करके मसले सुलझाने चाहिए। गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका में बैठकर भारत की संसद पर हमला करने और भारत में हिंसक गड़बड़ी फैलाने की धमकी दे रहा है, यह तो बाइडेन प्रशासन के लिए भारी शर्म की बात होनी चाहिए। बेहतर होगा कि अमेरिकी प्रशासन पन्नू के ख़िलाफ़ एक्शन लेकर भारत को भरोसे में ले।

आज का इतिहास

1913 दुनिया की पहली क्रॉस वर्ड पहेली, आर्थर वायने की वर्ड क्रास, न्यूयॉर्क वर्ल्ड में प्रकाशित हुई।
1919 लोगों को दो साल तक जेल में रखने के लिए जेल में भर्ती कराने के बाद, सैन्य अराजकतावादी एम्मा गोल्डमैन को संयुक्त राज्य अमेरिका से रूस भेज दिया गया।
1923 नेपाल और यूनाइटेड किंगडम ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जो एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को पहले से तय करता है।
1931 जेम्स स्किलिन ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री पद से इस्तीफा दिया।
1937 रंगीन चित्रों और आवाज वाली पहली कार्टून फिल्म-डिजनीस स्नो व्हाईट का प्रदर्शन किया गया।
1949 पुर्तगाली शासकों ने इंडोनेशिया को संप्रभु राष्ट्र घोषित किया।
1962 ब्रिटेन ने अमेरिका से पोलारिस मिसाइलों की खरीदने के लिए तैयार हुआ।
1963 ग्रीक और तुर्की साइप्रस के बीच अंतर - सांप्रदायिक लड़ाई शुरू हुई।
1965 संयुक्त राष्ट्र ने नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को अपनाया, जिस पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से 87 सदस्य हैं।
1968 केनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 8 का चंद्रमा की कक्षा के लिए प्रक्षेपण किया गया।
1971 कर्ट वॉल्डहाइम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चौथे महासचिव बने।
1974 पनडुब्बी प्रशिक्षण देने वाले देश के पहले पोत आईएनएस सतवाहन को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जहाजी बेडे में शामिल किया गया।
1988 पान एमफलाइट 103 के बोर्ड में बम विस्फोट होने पर कुल 270 लोग मारे गए थे, जबकि विमान स्कॉटलैंड के लॉकेरी में उड़ान भर रहा था।
1994 मेक्सिको का पॉपोकैपेटल ज्वालामुखी, 47 साल से निष्क्रिय, शुरुआत, और अब देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है।
2004 इराकी विद्रोहियों ने मोसुल के शहर में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया 22 लोग मारे गए।
2010 रग्बी यूनियन के खिलाड़ी माइक टिंडल की रानी एलिजाबेथ की पोती ज़ारा फिलिप्स की सगाई की घोषणा स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल ने की है।

सुरक्षा चूक को महंगाई और बेरोजगारी से जोड़ना गलत

डॉ. आशीष वशिष्ठ

पिछले दिनों लोकसभा की दर्शक दीर्घा से दो युवक सांसदों की मेज पर कूद गए। एक युवक ने जूते से कुछ निकाला और सदन के अंदर पीला धुआं छा गया। आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसद नेता राहुल गांधी से संसद में सुरक्षा चूक पर मीडिया ने सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी ब्रीच जरूर हुई है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी और महंगाई है। मोदी जी की पॉलिसीज के कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। राहुल के बयान के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक था। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को घेरते हुए बयान दिया है कि लोकसभा में विजिटर गैलरी से कूदने वाले आरोपी बेरोजगारी की समस्या पर देश का ध्यान खींचना चाहते थे। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या इस गंभीर एवं संवेदनशील मामले में राजनीति होनी चाहिए? क्या असल में इस घटना की वजह बेरोजगारी है?

जांच एजेंसियां आरोपियों से पूछताछ में जुटी हैं। उम्मीद है कुछ दिनों में सच भी सामने आ ही जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया विपक्षी दल अपने बयानों से आरोपियों का बचाव करते दिखाई दे रहे हैं। वास्तव में विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं की बयानबाजी सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगती है। आतंकी घटना को अंजाम देने वाले युवकों को बेरोजगारी से पीड़ित और कुंठित बताकर विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की जो तैयारी कर रही है, उसकी परतें धीरे-धीरे खुलने लगी हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में विपक्ष और इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को पराजित करने के सारे यत्न किए। लेकिन समझदार जनता ने विपक्ष की नीति और नीयत को अच्छे से पहचान कर न्याय कर दिया। हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में मतदाताओं ने कांग्रेस को जो पटखनी दी है, उसने कांग्रेस को बहुत गहरी चोट दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में समाजवादी पार्टी को भी काफी उम्मीदें थीं। लेकिन इस बार उसका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। ऐसे में विपक्ष और खासकर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को यह समझ नहीं आ रहा कि, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला वो कैसे करेंगे। लोकसभा चुनाव में वो जनता के सामने क्या मुद्दा और एजेण्डा लेकर जाएंगे।

असल में जन सरोकारों से दूर सत्ता पाने की बेचैनी में विपक्ष के पास मोदी सरकार को घेरने के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ऐसे में विपक्ष का सारा जोर इस बात पर है कि येन केन प्रकारेण मोदी सरकार की छवि को धूमिल किया जाए।

वर्ष 2014 में जब से मोदी सरकार ने देश की सत्ता संभाली हैं, तब से तमाम देशविरोधी ताकतें किसी ने किसी बहाने देश और मोदी सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिशें करती रहती हैं। देश में एक ऐसा गैंग हैं, जिसे देश में और देश से बाहर बैठी ताकतें खाद पानी उपलब्ध कराती हैं। आंदोलनजीवी ये गैंग देश विरोधी ताकतों के इशारे पर कभी शाहीन बाग, कभी किसान आंदोलन और कभी पहलवान आंदोलन के जरिये मोदी सरकार को घेरने और देश की प्रतिष्ठा धूमिल करने का काम करते हैं। इस गैंग ने नोट बंदी, धारा 370 को हटाते समय और कोविड काल में भी देश में अराजकता फैलाने की पूरी कोशिश की। लेकिन जनता इनके बहकावे में नहीं आई।

इस गैंग का मकसद किसी भी तरीके से देश में अस्थिरता और अराजकता का माहौल बनाना है। ऐसा करके वो देश के बुरे हालातों और घटनाओं को ठिकरा मोदी सरकार के सिर फोड़कर सत्ता प्राप्ति के मंसूबों में कामयाब होना चाहते हैं। इस गैंग ने देश हित में उठाये गये हर कदम का विरोध संसद से लेकर सड़क तक किया है। लेकिन जनता इस देश विरोधी गैंग के हथकंडों और प्रपंचों को अब समझने लगी है। इसलिए वो इनके झांसे में नहीं आती। हालिया विधानसभा चुनाव में जनता ने जिस विवेकशीलता का परिचय दिया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है।

संसद में हुई आतंकी घटना को बेरोजगारी से जोड़कर विपक्ष बड़ी चालाकी से युवाओं को भड़काना चाहता है। वो चाहता है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व युवा सड़कों पर उतरकर धरना, प्रदर्शन कर सरकार का विरोध करें जिससे सरकार की छवि को ठोस पहुंचे और चुनाव में वो लोगों की नाराजगी को अपने पक्ष में भुना सकें। बेरोजगारी पिछले दस वर्षों में पैदा हुई समस्या नहीं है। देश में छह दशक तक और राज्यों में सर्वाधिक समय तक कांग्रेस की सरकारें रही हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में बेरोजगारी से निपटने के लिए हुए कार्य सबके सामने हैं। अगर कांग्रेस ने अपने लंबे कार्यकाल में इस समस्या पर ढंग से काम किया होता तो आज बेरोजगारी की समस्या इतनी विकराल और गंभीर न होती। लेकिन जब केवल विरोध के लिए विरोध करना हो तो फिर तर्क, तथ्य और गंभीर प्रश्न नेपथ्य में चले जाते हैं।

राहुल और अखिलेश यादव आज युवाओं की बेरोजगारी का राग अलाप रहे हैं, उन्हें देश को बताना चाहिए कि जब उनके दल सत्ता में थे तो उन्होंने कितनी गंभीरता से इस बारे में कदम उठाये थे। केंद्र, राज्य और सार्वजनिक उद्यमों में लगभग तीन करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं। भारत में 70 करोड़ युवा है। सरकारी नौकरियां सिर्फ लाखों में हैं। इस जटिलता और स्थिति को समझना होगा। बेरोजगारी किसी एक व्यक्ति या परिवार की समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चिंता का विषय है। लेकिन राजनीतिक दलों को किसी भी गंभीर विषय पर तार्किक विमर्श करने की बजाय लोगों को अपने स्वार्थपूर्ति के लिए उकसाना होता है। आतंकी चरित्र के व्यक्तियों को बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दे से जोड़कर विपक्ष ने अपनी नीति और नीयत को साफ कर दिया है कि उसे बेरोजगारी से कोई लेना-देना नहीं है। उसका मकसद बेरोजगार युवाओं के कंधों पर चढ़कर सत्ता हासिल करना मात्र है।

संसद के बाहर की घटना में दो लोग शामिल थे। नीलम की उम 42 वर्ष है। वे बहुत नाराज़ हैं क्योंकि मोदी सरकार ने बेरोजगारी बढ़ा दी है। पर 2014 तक वे क्यों बेरोज़गार थीं? 32 साल की उम्र तक बेरोज़गार रहने पर उसे गुस्सा नहीं आया। अनमोल की उम्र 25 साल है। लोकसभा में दर्शक दीर्घा से कूदा युवक सागर शर्मा सिर्फ 12वीं पास है। और दूसरे युवक मनोरंजन डी की उम्र 35 साल है। इस घटना का मास्टर माइंड बताये जा रहे ललित झा की उम्र 40 साल है। मोदी सरकार के सत्ता संभालने के समय वह 30 साल से ऊपर का हो चुका था। उसे नौकरी मिल जानी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता राहुल गांधी बताएं कि ललित झा को यूपीए सरकार ने नौकरी क्यों नहीं दी, उसे बेरोजगार क्यों रखा? वैसे भी ललित बेरोजगार नहीं था। शिक्षक की नौकरी के साथ-साथ नीलाक्ष नाम के एनजीओ का महासचिव भी था।

सौम्यता सहजता के प्रतीक नव विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन

चन्द्र शेखर गंगराड़े

छठवीं विधान सभा के आम निर्वाचन उपरांत विधान सभा का गठन 4 दिसंबर, 2023 को हो गया और इसी के साथ छत्तीसगढ़ की छठवीं विधान सभा का सफर आरंभ हो गया है। 13 दिसंबर, 2023 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं उपमुख्यमंत्री के रूप में अरूण साव एवं विजय शर्मा की शपथ के साथ ही, छत्तीसगढ़ विधान सभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह होंगे, इस पर मुहर तो उसी दिन लग गई थी जब मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय के नाम पर केंद्रीय हाईकमान ने मोहर लगाई थी। 17 दिसंबर, 2023 को डॉ. रमन सिंह ने छठवीं विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में अपना नामांकन प्रस्तुत किया और 19/12/2023 को विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वानुमति से निर्वाचित हो गये है। डॉ. रमन सिंह के अध्यक्ष पद पर निर्वाचन की सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि उनके नाम के प्रस्तावक और समर्थकों में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉ. चरण दास महंत एवं निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल थे और वे नामांकन के समय उपस्थित भी थे। यह संसदीय लोकतंत्र का एक उत्कृष्ट एवं नायाब उदाहरण है। चुनाव की कड़वाहट को भूलकर विपक्ष ने भी अध्यक्ष के निर्वाचन में सकारात्मक पहल कर अध्यक्ष का निर्वाचन सर्वसम्मति से हो यह सुनिश्चित किया। छठवीं विधान सभा का प्रथम सत्र 19 दिसंबर, 2023 से प्रारंभ हुआ और प्रथम दिन ही माननीय सदस्यों को शपथ दिलाने के उपरांत, माननीय अध्यक्ष के निर्वाचन की कार्यवाही पूर्ण हुई। 15 अक्टूबर, 1952 को जन्मे डॉ. रमन सिंह प्रतिभा के धनी है लेकिन उनकी सादगी, सौम्यता, सहजता, सुलभता, सरलता,उदारता उनके ऐसे गुण हैं जिन्होंने उनको राजनीति में ऊँचाईयों पर पहुंचाया। प्रथम बार जब वे वर्ष 1990 में विधायक के रूप में अविभाजित मध्यप्रदेश की नवम् विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे तब उन्होंने एक विद्यार्थी की तरह विधान सभा की प्रक्रिया की बारीकियों को समझा और सीखा और उनकी इसी अध्यनशीलता के कारण जब वे वर्ष 1999 में लोकसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुए तो पहली बार में ही, उन्हें भारत सरकार में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया और वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का कार्यभार उन्होंने संभाला। तत्पश्चात् जब वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ की द्वितीय विधान सभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ तो उनकी इसी सादगी, सौम्यता और कार्य के प्रति लगन, निष्ठा के कारण ही पार्टी द्वारा उन्हें छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया और इन्हीं नैसर्गिक गुणों के कारण लगातार तीन बार उनके नेतृत्व में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री के रूप में जितनी सौम्यता और शालीनता के साथ पक्ष के विधायकों को सुनते थे, उतने ही शांत मन के साथ विपक्ष की आवाज को भी सुनते थे और कितनी ही विकट परिस्थिति रही हो, उन्होंने धैर्य के साथ सभी सदस्यों की बातों को न केवल सुना बल्कि आवश्यकता पढ़ने पर आक्रामक अंदाज में तथ्यों के साथ अपनी बात भी रखी। आज जब सादगी, सौम्यता, सहजता सुलभता विनम्रता की प्रतिमूर्ति को विधान सभा के सर्वोच्च पद पर बैठाया गया है तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में संसदीय गरिमा में और अभिवृद्धि होगी और छत्तीसगढ़ विधान सभा, अपनी पहचान के अनुरूप छठवीं विधान सभा के इस सफर में नई ऊँचाईयों को भी प्राप्त करेगी। उन्होंने अध्यक्ष पद पर निर्वाचन के उपरांत आपने पहले ही संबोधन में इस बात को व्यक्त भी किया कि वे इस विधानसभा के अभिभावक एवं मुखिया के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए विधानसभा की परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। डॉ. रमन सिंह बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के हैं। सभी सदस्यों की बात शांतिपूर्वक सुनना उनका स्वभाव है। और उनका यही गुण अध्यक्ष पद के दायित्वों के निर्वहन में कारगर साबित होगा और जिस प्रकार उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश को विकास की राह दिखाई वैसे ही छत्तीसगढ़ विधानसभा की गरिमा को भी ऊँचाइयों पर ले जाएँगे ऐसा विश्वास हैं।

पूरी राजनीति बदलती आधी आबादी

राजकुमार सिंह

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों का विभिन्न कोणों से विश्लेषण आगे भी जारी रह सकता है, लेकिन खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रचंड जीत में आधी आबादी की निर्णायक भूमिका मानी जा रही है। इसमें केंद्र सरकार से लेकर विभिन्न भाजपाई राज्य सरकारों द्वारा नारी सशक्तिकरण से लेकर महिलाओं को सीधे लाभ पहुंचानेवाली योजनाओं तक उठाए गए कदमों का भी परिणाम है। तेलंगाना भी महिला केंद्रित योजनाओं और चुनावी वायदों में अपवाद नहीं रहा, जहां कांग्रेस को जनादेश मिला है, लेकिन भाजपाई जीतवाले राज्यों में महिला मतदाताओं का रुझान इस कोण से गहन विश्लेषण की जरूरत रेखांकित करता है।

देश में सक्रिय राजनीति की तरह, मतदान प्रक्रिया में भी महिलाओं की भागीदारी बहुत उत्साहवर्धक नहीं रही है, लेकिन वर्ष 2014 के बाद स्थिति बदलती दिख रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां 67.1 प्रतिशत पुरुषों ने मतदान किया, वहीं मतदान करनेवाली महिलाओं का प्रतिशत 67.18 रहा। आंकड़े बताते हैं कि महिला मतदाताओं का ज्यादा वोट भाजपा की झोली में जा रहा है। नरेंद्र मोदी जब भाजपा का चेहरा बने, तब 2014 के चुनाव में भाजपा को मात्र 29 प्रतिशत महिला वोट ही मिले थे, लेकिन 2019 के चुनाव में यह प्रतिशत बढ़ कर 36 पर पहुंच गया। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तो भाजपा को 46 प्रतिशत महिला मत मिले। पितृसत्तात्मक भारतीय समाज के मद्देनजर यह भी बड़ा सकारात्मक बदलाव है कि महिलाएं वोट देने के लिए दल और उम्मीदवार का चयन खुद कर रही हैं। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे के अलावा सार्वजनिक शौचालय, बैंक खाते, हर घर नल से जल और उज्ज्वला जैसी योजनाएं महिला मतदाताओं के बड़े वर्ग को आकर्षित करने में सफल हैं। भाजपाई मुख्यमंत्रियों ने भी महिला मतदाताओं को प्रभावित-लाभान्वित करनेवाली योजनाएं लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। शिवराज सिंह चौहान के 18 साल के शासन में महिलाओं को लाभान्वित करनेवाली 21 योजनाएं चलीं। छत्तीसगढ़ में शायद ही किसी को भाजपा की जीत का विश्वास रहा हो, पर उसने अंतिम दिनों में महतारी वंदन योजना में हर विवाहित महिला को 1000 रुपए मासिक देने का वायदा ही नहीं किया, बाकायदा लाखों फॉर्म भी भरवा लिए और कार्यकर्ताओं ने फोन करके योजना के फायदे विस्तार से बताना शुरू कर दिया। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने महिलाओं समेत कमोबेश सभी जरूरतमंद वर्गों के लिए चुनाव से चंद महीने पहले लोक लुभावन योजनाओं-घोषणाओं की बारिश-सी कर दी थी, पर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के आंकड़ों के सहारे भाजपा ने बाजी पलट दी।

असम में क्या बंट जाएगा मुस्लिम वोट बैंक

रविशंकर रवि

असम में इन दिनों एक दिलचस्प बहस चल रही है, देसी मुसलमान और कथित विदेशी मुसलमान को लेकर। राज्य सरकार ने भारतीय मूल के असमिया मुसलमानों के पांच समुदायों- गोरिया, मोरिया, देसी, सैयद और जुलाहा को खिलंजिया (असम के भूमि पुत्र) का दर्जा दिया है। असम सरकार के इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में जैसे भूचाल आ गया है। अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाले नेताओं में इस फैसले से बेचैनी है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की इस पहल से मुस्लिम वोट बैंक विभाजित हो गया है।

असल में, बांग्लादेशी मूल के मुसलमानों की तुलना में भारतीय मूल के असमिया मुसलमान खुद को श्रेष्ठ मानते हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी पहचान बांग्लादेश मूल के मुसलमानों के साथ की जाए। इसलिए असम में बसे असमिया मुसलमानों के बीच सरकार के इस फैसले से खुशी की लहर है। सरकार का कहना है कि असमिया मुसलमानों को विशेष मान्यता दी गई है, क्योंकि वे उस समाज के अंग हैं। मुसलमान होने से उनकी भाषा, संस्कृति और रहन-सहन में विशेष अंतर नहीं है। यह समझना जरूरी है कि असम में दो तरह के मुसलमान हैं। एक को स्थानीय मुसलमान कहा जाता है और दूसरे को स्थानीय बोली में मियां मुसलमान कहते हैं।

स्थानीय मुसलमान पूरी तरह असमिया संस्कृति में रचे-बसे हैं। उनकी भाषा भी असमिया है। उनका रहन-सहन और वेशभूषा स्थानीय समाज की तरह है। इनमें कुछ लोग मुगल शासन काल में देश के विभिन्न हिस्से से यहां आए थे। मुगल सेना की पराजय के बाद यहीं रह गए। आहोम शासकों ने इन्हें ऊपरी असम में बसा दिया। स्थानीय मुसलमानों में ही कुछ लोग कोच राजवंशी समुदाय के हैं, जो इस्लाम धर्म के प्रभाव में आकर मुसलमान हो गए। इसी समुदाय के धार्मिक नेता अजान फकीर ने असम में धार्मिक

गीत परंपरा-जिकिर और जारी की रचना की, जिसे स्थानीय परंपरागत वाद्ययंत्रों के साथ गाया जाता है। मियां मुसलमान मूल रूप से बांग्ला बोलते हैं और आजादी के पहले या बाद में बांग्लादेश से आकर असम में बसे हैं। वे लुंगी और टोपी पहनते हैं। उनमें ज्यादातर मजदूरी और खेती करते हैं। वे शैक्षणिक रूप से भी पिछड़े हैं। ये लोग पहले निचले असम में वास करते थे, लेकिन अब धीरे-धीरे नगांव, मोरीगांव और दरंग जिलों में फैल चुके हैं। असमिया मुसलमानों के अधिकांश बच्चे असमिया माध्यम के सरकारी या निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। वे बीहू भी पूरे उत्साह से मनाते हैं। आम असमी की तरह कपड़े पहनते और घर के अंदर भी असमिया बोलते हैं। घुसपैठ विरोधी आंदोलन से असमिया मुसलमान खुद को असहज महसूस करते रहे हैं। अल्पसंख्यक विरोधी अभियान का खामियाजा उन्हें भी भुगताना पड़ता रहा है। इसलिए वे मियां मुसलमान से खुद को अलग रखना चाहते हैं। असमिया मुस्लिम अपनी भाषाई, जातीय और धार्मिक पहचान के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें थोलुवा मुसलमान या खिलंजिया मुसलमान के नाम से भी जाना जाता है। ये असमिया पहचान और राष्ट्रीयता के साथ एकीकृत हैं। असम की राजनीति में अल्पसंख्यकों का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था। राज्य की कुल आबादी में मुसलमानों की आबादी तीस फीसदी से अधिक है। वे विधानसभा की कुल 126 सीटों में करीब 30 सीटों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। असम में बीजेपी सरकार आने के बाद से इस स्थिति को बदलने के तरीकों पर सोच-विचार शुरू हो गया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने असमिया मुसलमानों की अलग पहचान बनाए रखने की बेचैनी को परख लिया और उस दिशा में रणनीति बनाने लगे।

माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने मुसलमान आबादी को विभाजित करने के लिए असमिया मुसलमान और मियां मुसलमान कार्ड खेला है। इसलिए असमिया मुसलमानों को अलग पहचान देने की वैधानिक प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। असम सरकार ने खिलंजिया (असमिया) मुसलमानों की स्थिति पर अध्ययन के लिए वरिष्ठ पत्रकार वसबीर हुसैन की अध्यक्षता में गत 31 जुलाई 2021 को एक उप-समिति के गठन की अधिसूचना जारी की। इसमें असमिया मुसलमानों के प्रबुद्ध लोगों को शामिल किया गया। उसी वर्ष दिसंबर में उप-समिति की रिपोर्ट आ गई, जिसमें गोरिया, मोरिया, देसी और जुलाहा समुदायों को खिलंजिया (असम के भूमि पुत्र) का दर्जा देने की सिफारिश की गई।

बाद में असम सरकार ने इन समुदायों को खिलंजिया मुसलमान के रूप में मान्यता दे दी। वसबीर हुसैन की अध्यक्षता वाली इस उप-समिति ने असमिया मुललमानों के विकास के लिए एक अलग विभाग खोलने की सिफारिश भी है। इससे साफ है कि असम में मुसलमान दो खेमे में बंट गए हैं। इससे अल्पसंख्यकों के आधार पर राजनीति करने वाले मौलाना बदरुद्दीन अजमल जैसे नेता परेशान हैं। इस फैसले को राजनीतिक रूप से अल्पसंख्यकों की ताकत कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे मुख्यमंत्री हिमंता का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है।

हाल ही में असम में परिसीमन का काम पूरा हुआ है, जिसमें अल्पसंख्यक बहुल इलाके वाले विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे अल्पसंख्यक बहुल इलाकों को जोड़ दिया गया है। परिसीमन का हिंदू बहुल विधानसभा क्षेत्रों के साथ ही लोकसभा क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ेगा। यह कहा जा सकता है कि असम की राजनीति में अल्पसंख्यकों का विस्तार रोकने के लिए उन्हें विभाजित कर दिया गया है।

जीत की हैट्रिक के लिए अयोध्या और हिन्दुत्व फिर से भाजपा के एजेंडे में

अजय कुमार

हिन्दुस्तान के इतिहास में एक और नई इबारत जुड़ने जा रही है। अगले साल 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के नवनिर्मित आलीशान मंदिर में प्रभु श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसी के साथ पांच सौ साल का विवाद भी इतिहास के पन्नों में सिमट जायेगा। प्राण प्रतिष्ठा की खबर से रामभक्त प्रसन्न हैं। वहीं इसको लेकर सियासत भी गरमाना शुरू हो गई है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी रामलला के इर्दगिर्द घूमता नजर आये तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिये। क्योंकि बीजेपी एक बार फिर ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। वैसे भी करीब चार दशक से अयोध्या राजनीति का केन्द्र बना हुआ है। बीजेपी रामलला के नाम पर कई चुनाव लड़ और जीत चुकी है। पूरे देश में बीजेपी का विस्तार यदि देखने को मिल रहा है तो इसकी जद में अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्रमुख भूमिका रही है। इसी के चलते भले ही आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा हो, लेकिन बीजेपी भी इसका श्रेय लेने में पीछे नहीं है। वह अपने वोटरों को बताती रहती है कि यदि वह नहीं होती तो रामलला का मंदिर निर्माण हो ही नहीं पाता। खास बात यह है कि बीजेपी के इस दावे पर उसके वोटर विश्वास भी करते हैं।

बहरहाल, एक तरफ बीजेपी के उत्थान में रामलला का मंदिर मील का पत्थर साबित हुआ है तो दूसरी ओर अयोध्या की सियासत के चलते कई राजनैतिक दलों को पतन का भी सामना करना पड़ा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की आज जो दुर्दशा देखने को मिल रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बीजेपी को छोड़कर अन्य सियासी दल अपने आप को इस सियासत में एडजेस्ट नहीं कर पाये। इसीलिए कोई भी गैर-बीजेपी दल नहीं चाहता है कि 2024 का आम चुनाव रामलला के नाम पर लड़ा जाये। इसको लेकर कई दलों में बेचैनी भी देखी जा सकती है। इसकी बानगी हाल में ही तब देखने को मिली जब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंचे सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान श्रीराम के मंदिर का निर्माण कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की इसमें कोई भूमिका नहीं है। शिवपाल ने आरोप लगाया कि भाजपा भगवान श्रीराम के नाम पर राजनीति कर देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। शिवपाल का यह बयान सहारनपुर में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी के सिलसिले में अपने समर्थकों से संवाद के बाद मीडिया से रूबरू होने के दौरान सामने आया। सहारनपुर के दो दिवसीय दौरे के दौरान शिवपाल ने देवबंद में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद वह मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। इस मौके पर शिवपाल यादव ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया। शिवपाल यादव ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्रीराम का मंदिर निर्माण कार्य कोर्ट के आदेश पर किया जा रहा है। भाजपा सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। शिवपाल जैसी भाषा करीब-करीब सभी दलों के नेता बोल रहे हैं।

वहीं बीजेपी वालों को इससे सियासी फायदा होता दिख रहा है।

राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अधिकांश केंद्रीय मंत्री रामलला से जुड़ी तमाम खबरें अपने सोशल साइट्स पर पोस्ट कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर तमाम बीजेपी नेता तक अयोध्या से जुड़ा वीडियो शेयर करते रहते हैं। गौरतलब है कि इसी साल की शुरुआत में जनवरी महीने की बात है जब त्रिपुरा की एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि राहुल गांधी सुन लें जनवरी 2024 में बन जाएगा रामलला का मंदिर। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि 2019 के चुनाव के दौरान जब मैं बीजेपी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस अध्यक्ष थे। वे रोज पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे तिथि नहीं बताएंगे। अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो अगले साल 1 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर आपको तैयार मिलेगा।

उधर, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि राम मंदिर का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। भारतीय हजारों वर्षों से राम की पूजा करते आ रहे हैं। अचानक, मोदी राम भक्त बन गए हैं और देश को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी ने कहा कि 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन के लिए केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही निमंत्रण क्यों दिया गया है? विपक्षी दलों के नेताओं ने सवाल किया कि क्या यह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक पार्टी कार्यक्रम बन जाएगा? कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने पूछा कि क्या सिर्फ एक ही पार्टी को निमंत्रण भेजा जा रहा है? क्या यह अब एक पार्टी कार्यक्रम बन गया है? भगवान सबके हैं। हर पार्टी को निमंत्रण मिलना चाहिए था। एक तरफ गैर बीजेपी पार्टियां इस बात से गुस्से में हैं कि बीजेपी रामलला के नाम पर सियासत कर रही है वहीं बीजेपी पर्दे के पीछे से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के काम को चुनावी इवेंट बनाने में लगी है। इसी कड़ी में अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्रीराम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी चरण पादुकाएं भी रखी जाएंगी। फिलहाल ये पादुकाएं देशभर में घुमाई जा रही हैं। पादुकाएं प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले 19 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगी। ये चरण पादुकाएं एक किलो सोने और सात किलो चांदी से बनाई गई हैं। इन्हें हैदराबाद के श्रीचल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने बनाया है। 17 दिसंबर को इन्हें रामेश्वर धाम से अहमदाबाद लाया गया था। यहां से यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग धाम, द्वारकाधीश नगरी और इसके बाद बद्रीनाथ ले जाई जाएंगी। श्रीचल्ला श्रीनिवास इन पादुकाओं को हाथ में लेकर अयोध्या में निर्माणाधीन मंदिर की 41 दिन की परिक्रमा भी कर चुके हैं।

अयोध्या में श्रीरामलला की प्राण-प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, इसके लिए पटना के महावीर मंदिर में तैयारी चल रही है। अयोध्या में इस महा आयोजन में शामिल होने वाले भक्तों को अपनी राम रसोई से स्वादिष्ट भोजन कराया जायेगा। 15 जनवरी से हर महीने 6 लाख लोगों को भोजन कराने की तैयारी है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक चलने वाली राम रसोई अयोध्या में बिहार की खास पहचान बनेगी। वहीं श्रीराम मंदिर परिसर में 10 हजार स्क्वॉयर फीट में राम रसोई बनाने का प्लान भी है। अभी राम लला के सामने स्वर्णिम दीपक भी महावीर मंदिर से भेजे गए गाय के घी से जलाया जाएगा। वहीं सात समुंदर पार अमेरिका में रह रहे हिंदू समुदाय ने वॉशिंगटन डीसी में फ्रेडरिक सिटी मैरीलैंड में एक कार रैली का आयोजन किया। इसके साथ ही यहां एक महीने तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत की हो गयी है। रैली के लिए सभी श्री भक्त अंजनेय मंदिर में इकट्ठा हुए। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक के लिए अयोध्या और हिन्दुत्व को फिर से बीजेपी ने अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है।

क्या खुबानी खाने के फायदे जानते हैं आप?

रोज इतने खाए तो दूर रहेंगी कई बीमारियां!

खुबानी या एप्रीकॉट एक सुखा ड्राई फ्रूट्स होता है. इस ड्राईफूट्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन इसके फायदे गजब के होते हैं. इसमें विटामिन ए, बी, सी और ई प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. इसके अलावा पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, फॉस्फोरस जैसे खनिज लवण तथा फाइबर भी खुबानी में मौजूद होते हैं. ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बेहद लाभदायक होते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, सर्दियों में रोजाना पांच से छह खुबानी खाना काफी है. खुबानी की तासीर गर्म होता है. यह शरीर को अंदर से गर्म रखती है और सर्दी-जुकाम से बचाती है. सर्दियों में खुबानी खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बीमारियों से लडने में मदद मिलती है. आइए जातने हैं यहां खुबानी के फायदे...

आइए जानते हैं खुबानी कब खाना चाहिए

खुबानी के इतने सारे फायदे हैं कि अगर इस रोजाना अपनी डाइट में शामिल किया जाए तो आँखों की रोशनी से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचा जा सकता है. रोजाना केवल 5-6 खुबानी खाना ही प्राप्त होती है. इसे खाली पेट या फिर नाश्ते के साथ लिया जा सकता है. दोनों समय इसे खाने के कई फायदे हैं.

हृदय रोगों के लिए फायदेमंद

खुबानी में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. खुबानी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन आदि फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करते हैं जो हृदय रोगों का एक प्रमुख कारण हैं. इसके अलावा, खुबानी में उच्च मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है. फाइबर एलडीएल यानि बुरे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है जो एथेरोस्क्लेरोसिस (धमनियों का संकरा होना) का एक प्रमुख कारक है.

डायबिटीज के लिए फायदेमंद

खुबानी मधुमेह या डायबिटीज जैसी बीमारियों से लडने में बहुत प्रभावी है. इसका कारण यह है कि खुबानी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है. इसलिए यह डायबिटीज मरीज़ों को अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखने में मदद करता है. रोजाना खाने से इसके कई फायदे मिलते हैं.

पाचन के लिए फायदेमंद

खुबानी में फाइबर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है. इसमें में कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है जो भूख कम करता है और वजन कम करने में भी मदद करता है.

कैंसर में फायदेमंद

खुबानी में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स कैंसरोगेनेसिस को रोकने में मदद कर सकते हैं. इसके अलावा, खुबानी में मौजूद विटामिन ए, सी और ई भी शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फ्री रेडिकल्स से लड़कर कोशिकाओं की रक्षा करते हैं.

सर्दियों में खाएं ये गर्म तासीर वाली चीजें, कंपकंपाती ठंडी में भी आपकी बॉडी रहेगी अंदर से गर्म

शहद

शहद को बेहद ही गर्म तासीर का माना जाता है. सर्दियों में इसका सेवन करना सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित हो सकता है. शहद विटामिन,मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है. शहद का सेवन आप सर्दी, जुखाम और गले में दर्द होने पर भी कर सकते हैं, ये ऐसी परेशानियों में बेहद ही फायदेमंद साबित होता है.

गुड़

गुड़ एक बेहद ही अच्छी सामग्री है जिसका सेवन कई लोग साल भर करते हैं. सर्दियों में खासकर से लोग गुड़ का सेवन ज्यादा करते हैं क्योंकि गुड़ आपके शरीर को गर्म रखता है. आप गुड़ का सेवन गुड़ की चाय या गुड़ की मिठाइयां बनाकर कर सकते हैं. गुड़ हमारे शरीर को कैलोरी देने में भी मदद करता है.

देसी घी

देसी घी सेहत के लिए एक बेहद ही फायदेमंद सामग्री है . बड़े बुजुर्ग हमेशा से हमें घी खाने की सलाह देते आए हैं. देसी घी में विटामिन,मिनरल्स,ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं. देसी घी आप के शरीर को बेहद गर्म रखता है और आप के पाचन शक्ति को भी बेहतर बनाता है. सर्दियों में आप रोटी में घी लगाकर खा सकते हैं या खिचड़ी या सूप में घी डालकर घी का सेवन कर सकते हैं.

तिल

तिल का बेहद ही सेवन अक्सर ठंड में किया जाता है. ठंडी घुसते ही बाजार में हमें तिल की बनी हुई सामग्रियां देखने को मिलती है. तिल इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी मदद करता है. तिल और गुड़ के बने हुए लड्डू अक्सर लोग बड़े ही चाव से खाते हैं.

अदरक

अदरक आपकी इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद साबित होता है. अदरक की तासीर बेहद ही गर्म होती है. सर्दियों में अक्सर लोग अदरक की चाय या अदरक के काढ़े का सेवन करते हैं.

दालचीनी

दालचीनी हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है जिसके कारण हमारे शरीर में गर्माहट पैदा होती है. खांसी की समस्या में आप दालचीनी के पानी का सेवन कर सकते हैं. दालचीनी एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुणों से भरपूर होता है.

ड्राई फ्रूट्स

ड्राई फ्रूट्स यूं तो लोग साल भर खाते हैं लेकिन सर्दियों में खास तौर से ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए. ड्राई फ्रूट्स हमारे शरीर को गर्म रखता है और सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से बचाव करता है. आप बादाम ,काजू, किशमिश , अखरोट, अंजीर, और खजूर जैसे ड्राई फ्रूट्स का सेवन ठंड से बचने के लिए कर सकते हैं.

सर्दियों में बच्चे की मालिश करने के लिए इस्तेमाल करें ये तेल, बीमारी रहेगी कोसों दूर

तेल मालिश करवाने से मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं। इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है। इसलिए बच्चों को तेल मालिश करने की सलाह दी जाती है। ठंड के मौसम में भी बच्चों की तेल मालिश की जाती है। लेकिन सर्दी के मौसम में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा की आप किस तेल से बच्चे की मालिश कर रही हैं। मौसम के अनुसार आपको सही तेल चुनना चाहिए, क्योंकि ये मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। जानिए, सर्दियों के मौसम में बच्चों की किस तेल से मालिश करें-

तिल का तेल- तिल के तेल को मीठा तेल भी कहा जाता है। बच्चे की मालिश के लिए ये तेल अच्छा माना जाता है। सर्दी के मौसम में ये तेल बच्चे की स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है।

सरसों का तेल- सरसों के तेल को हल्का गुनगुना करें और फिर इससे बच्चे की मालिश करें। इस तेल में लहसुन और मेथीदाना को मिलाकर गर्म करें और फिर मालिश कर सकते हैं। बच्चों की हड्डियों और मांसपेशियों के लिए सरसों का तेल फायदेमंद होता है।

बादाम का तेल- बादाम का तेल पोषक तत्व और मॉइस्चराइज करने वाले गुणों से भरपूर होते हैं। यह तेल शरीर को गरमाई देता है। ऐसे में सर्दी के मौसम में इससे मालिश करना सबसे अच्छा है। बादाम के तेल में विटामिन ई और कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, जो बालों और स्किन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। ये तेल रंगत निखारने में भी मदद करता है और इससे बच?चे की हड्डियां मजबूत होती हैं।

कम उम्र के युवा भी हो रहे ऑस्टियो आर्थराइटिस का शिकार, खतरनाक होता है रिप्लेस

आज से 30 साल पहले 1990 में हमारे देश में ऑस्टियो आर्थराइटिस के करीब 2.3 करोड़ मामले थे। लेकिन साल 2019 में यह संख्या 6.2 करोड़ के पास पहुंच गई है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि ऑस्टियो आर्थराइटिस के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस बीमारी का सिर्फ बूढ़े ही लोग नहीं बल्कि युवा भी शिकार हो रहे हैं। हांलाकि लोग सोचते हैं कि हम जितनी सीढ़ियां चढ़ेंगे और जितना अधिक चलेंगे, हमारे ज्वाइंट्स उतने ज्यादा मजबूत होंगे।

लेकिन बता दें कि घर, ऑफिस और रोड आदि पर मौजूद हार्ड सरफेस, हील, बिना कुशन वाले जूते और सख्त सोल वाले फुटवियर की वजह से घुटनों का कार्टिलेज जल्द खराब हो जाता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस एक तरह का गठिया होता है। यह समस्या पहले अधिकतर बुजुर्गों में देखने को मिलती थी। लेकिन आज के समय में कम उम्र के लोगों में भी यह समस्या देखने को मिल रही है। इसका मुख्य और सबसे बड़ा कारण हमारी लाइफस्टाइल है। शरीर में विटामिन डी, कैल्शियम की कमी के साथ लो फिजिकल एक्टिविटी ऑस्टियो आर्थराइटिस के लिए जिम्मेदार होती है। यह सारी चीजें फ्यूचर में घुटनों के कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाते हैं। उम्र के साथ या ज्यादा काम करने से घुटनों का कार्टिलेज नहीं घिसता है। कई बार बुजुर्गों में भी यह एकदम दुरुस्त रहता है, तो कई बार यह कम उम्र में भी खराब हो जाता है। लेकिन अगर यह एक बार खराब हो जाता है, तो यह दोबारा रिजनरेट नहीं होता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं हड्डी एक बार टूट जाए, तो वह दोबारा जुड़ सकती है, लेकिन ऑस्टियो आर्थराइटिस में खराबी हो जाए तो कार्टिलेज दोबारा रिपेयर नहीं हो सकता है। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए आपको समय रहते कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको ऐसी कुछ बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको ध्यान में रखकर इस समस्या से बचा जा सकता है।

जानिए क्या है ऑस्टियो आर्थराइटिस

जैसे कार के पहियों में स्टील के फ्रेम में टायर लगे होते हैं, जो रोड पर पड़ने वाले झटकों को कम करते हैं और एक कुशन (गद्दी) का काम करते हैं। वैसे ही हमारी हड्डियों के बीच में कार्टिलेज की गद्दी होती है, जो इन्हें सेफ रखने में मदद करती है। वैसे तो ये सभी जॉइंट्स के बीच में होता है, लेकिन पैरों के कार्टिलेज ऑस्टियोआर्थराइटिस के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। दरअसल गाड़ी के टायर की तरह ये कार्टिलेज भी घिसते रहते हैं। और अगर ये पूरी तरह खराब हो जाएं तो दर्द भी बढ़ जाता है और घुटने बदलने भी पड़ सकते हैं।

युवाओं को भी हो रही ये बीमारी

बुजुर्गों को होने वाली ऑस्टियो आर्थराइटिस जैसी बीमारी आजकल युवाओं में भी तेजी से देखने को मिल रही है। युवाओं में इस बीमारी के होने का मुख्य कारण खराब लाइफस्टाइल, इंडियन टॉयलेट, स्मोकिंग और फिजिकल एक्टिविटी है। जिसकी वजह से युवाओं की मसल्स कमजोर हो जाती हैं। लेकिन नीचे बताए गए तरीकों को फॉलो कर इसे मैनेज किया जा सकता है।

एक्सरसाइज है जरूरी

हमारे शरीर का पूरा भार घुटनों पर पड़ता है। वहीं शरीर के सबसे ज्यादा मूवमेंट वाला हिस्सा भी पैर के जॉइंट्स होते हैं। इसलिए कार्टिलेज को बचाने के लिए पैरों के मसल्स का मजबूत होना जरूरी होता है। जिससे कि जॉइंट्स पर ज्यादा दबाव न पड़े और वह हेल्दी रहे। शरीर के वजन का सीधा असर घुटनों और कार्टिलेज पर पड़ता है। इस पर हमारे शरीर का जितना अधिक वजन पड़ता है।

प्रेग्नेंसी में हो सकता है दिल की बीमारियों का खतरा,इन संकेतों को न करें इग्नोर

गर्भावस्था एक ऐसा समय है जिस वक्त गर्भवती महिलाओं के खास केयर की जरूरत होती है ताकी जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे. इस दौरान कई स्वास्थ्य जटिलाओं के बीच दिल का भी खास ख्याल करना जरूरी होता है.

दिल की बीमारियों का भी खतरा

प्रेग्नेंसी के दौरान हेल्थ केयर को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्रेग्नेंसी में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी प्रभावित होता है क्योंकि उस दौरान भ्रूण को ज्यादा खून की जरूरत होती है. यूं तो प्रेग्नेंसी में और भी कई दिक्कतों से जूझना पड़ता है जैसे कि वजन का बढ़ना, गैस की प्रॉब्लम्स लेकिन इसी के साथ दिल की बीमारियों का भी खतरा बना रहता है. आपको भी इस दौरान अगर कुछ संकेत नजर आए तो इन्हें इग्नोर ना करें. तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें

पैर, हाथ और कंधों में सूजन दिखाई देना

यूं तो सूजन प्रेग्नेंसी में एक आम दिक्कत है लेकिन अगर ये आप को बार - बार और लगातार होने लगे तो ये हार्ट की बीमारी का एक संकेत हो सकता है.

छाती में दर्द बिल्कुल भी टालने की चीज नही है. अगर आप को एक या दो बार भी छाती में चुभन या जोर का दर्द महसूस हो तो तुरंत आप किसी डॉक्टर से मिलें.

ऐसे तो प्रेग्नेंसी में चक्कर आना एक आम निशानी है लेकिन अगर आप को रोजाना चक्कर आने की समस्या हो रही है तो ये दिल की बीमारी का संकेत हो सकता है.

थकान या हार्टबीट का तेज हो जाना

अगर आप कम काम करके या मामूली दूरी चल के थक जा रहे हैं और मामूली सीढ़ियां चढ़ने में आपकी सांस फूल जा रही है तो आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं क्योंकि ये हार्ट की समस्या का एक संकेत हो सकता है.

अगर आपको रात को नॉर्मल से कई ज्यादा बात यूरिन आने की दिक्कत आ रही है तो इसे नॉर्मल न समझें, ये हार्ट की बीमारी का भी इशारा हो सकती है.

अगर आप प्रेग्नेंसी में जरूरत से ज्यादा खांसती हैं या जब खांसी आती है तो रुकने का नाम नहीं लेती या लगातार दवाइयों के बाद भी आपको खांसी की शिकायत रहती है इसे गंभीरता से लें

सांस लेने में तकलीफ या सांस से संबंधित कोई भी परेशानी अगर आपको दिखे तो पहले किसी डॉक्टर से मिलें अगर नॉर्मल दवाइयों से ये दिक्कत ठीक न हो तो फौरन किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से मिलें.

अगर आप को प्रेग्नेंसी में रोज घबराहट होती है या आप जब सोने जाती हैं तो आप को बहुत डर लगता है या आप का मन घबराया सा लगता है और ये चीजें बार - बार हो रही हैं तो ये हार्ट की बीमारियों का एक संकेत हो सकता है.

संतरा बनाम कीनूः जानिए इनके बीच का अंतर और इनके स्वास्थ्य

अक्सर कुछ लोग बाजार से संतरे की बजाय कीनू खरीद लेते हैं क्योंकि एक जैसे दिखने के कारण कभी-कभी दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है।संतरा और कीनू सर्दियों के दौरान खाए जाने वाले 2 अलग-अलग खट्टे फल हैं, जो स्वाद और पोषक तत्वों के मामले में भी एक-दूसरे से भिन्न होते हैं।आइए आज हम आपको इन फलों के बीच के अंतर और स्वास्थ्य संबंधी लाभों के बारे में बताते हैं।

कीनू और संतरे के बीच का मुख्य अंतर

कीनू संतरे से अधिक रसदार होता है और इसकी खेती ज्यादातर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और हरियाणा में की जाती है।इसके अतिरिक्त अगर रंग की बात करें तो संतरे का रंग नारंगी, केसरिया और हरे तक हो सकता है, जबकि कीनू अक्सर गहरे नारंगी रंग का होता है।साथ ही संतरे का छिलका पतला और कीनू का छिलका मोटा होता है।यहां जानिए संतरे के फायदे।

इन फलों का स्वाद और कीमत

ये फल दिखने में भले ही समान हों, लेकिन इन दोनों का स्वाद काफी अलग होता है। संतरे स्वाद में मीठे होते हैं, जबकि कीनू अधिक रसदार और खट्टे स्वाद वाले होते हैं।हालांकि, संतरे की तुलना में कीनू की उपज ज्यादा होती है, जिस कारण इनकी कीमत कम होती है। इसका मतलब है कि संतरा कीनू से अधिक महंगा होता है।यही नहीं, बाजारों में संतरे की तरह-तरह की किस्में भी मौजूद हैं, जिनके भाव अलग-अलग हैं।

फलों में मौजूद पोषक तत्व

कीनू विटामिन- सी, विटामिन- बी कॉम्प्लेक्स, सोडियम, पोटैशियम, कैल्शियम और कॉपर जैसे खनिजों से भरपूर होता है। कीनू में अन्य खट्टे फलों की तुलना में लगभग 2.5 गुना अधिक कैल्शियम होता है।संतरे में विटामिन- सी की अधिक मात्रा होती है। एक मध्यम आकार के संतरे में लगभग 70 मिलीग्राम विटामिन- सी होता है। इसके अलावा इसमें थायमिन, फोलेट और पोटैशियम भी होता है।

दोनों फलों में से किसका चयन करना चाहिए?

अब बारी आती है यह उलझन दूर करने की कि संतरे और कीनू में से किसका सेवन स्वास्थ्य के लिए ज्यादा बेहतर है।कीनू के कुछ पौष्टिक तत्व संतरे से थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन कैलोरी के मामले में संतरा बेहतर है। इसलिए सीमित मात्रा में संतरे का सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।हालांकि, ऐसा नहीं है कि कीनू के सेवन से कोई नुकसान होता है, इसलिए इसे भी अपनी डाइट में शामिल करें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

भारत-अमेरिका के संबंध नहीं बिगड़ेंगे : पीएम मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अमेरिका द्वार लगाए गए आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित तौर पर हत्या की साजिश में भारत की संलिप्तता के दावे पर पीएम मोदी ने अब जवाब दिया है। एक विदेशी अखबार को दिए एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा है कि अगर हमारे ऊपर इस तरह के आरोप अगर लगते है तो हम उसपर जरूर गौर करेंगे। उन्होंने कहा बयान देते हुए कहा कि हम पहले सबूत की तलाश करेंगे साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी घटनाओं की वजह से भारत और अमेरिका के संबंध में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगर हमें कोई जानकारी देता है तो हम निश्चित रूप से उस पर गौर करेंगे। पीएम मोदी ने यह कहा है कि अगर हमारे किसी नागरिक ने कुछ भी अच्छा या बुरा किया है, तो हम उस पर गौर करने के लिए तैयार हैं। हमारी प्रतिबद्धता कानून के शासन के प्रति है।

मेरा इरादा कभी किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था : बनर्जी

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा और राज्यसभा से 1411 सांसदों के निलंबन के बाद धरना-प्रदर्शन के दौरान तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा कथिततौर पर राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस विवाद में सत्ताधारी भाजपा सांसद कल्याण बनर्जी पर हमलावर है, वहीं दूसरी ओर विवाद पर खुद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि उनका इरादा किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने का नहीं था। हालांकि तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।इस पूरे प्रकरण में खुद राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ ने निराशा व्यक्त की है और कल्याण बनर्जी के व्यवहार को हास्यास्पद और शर्मनाक बताया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि भला कोई सांसद कैसे इस हद तक जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पद के हुए अपमान के प्रति नाराजगी व्यक्त की।

उपराष्ट्रपति के अपमान पर राष्ट्रपति मुर्मू ने जताई निराशा

नईदिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद परिसर में उपराष्ट्रपति की नकल उतारे जाने पर कहा है कि जिस तरह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अपमानित किया गया है, उससे बेहद निराश हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट कर अपनी नाराजगी जताई है। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी थी, जिसके बाद विवाद बढ़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने पोस्ट में लिखा है- निर्वाचित प्रतिनिधि अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन उनकी अभिव्यक्ति मर्यादा के दायरे में होनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह उपराष्ट्रपति से इस मसले पर बात की है। कल्याण बनर्जी जिस वक्त उपराष्ट्रपति की नकल उतार रहे थे, उस वक्त वहां कई सांसद मौजूद थे, यहां तक कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी वहां मौजूद थे और घटना का वीडियो बना रहे थे।

ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल

नईदिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बुधवार को 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान पाठ्यक्रम के लिए रवाना हुए। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समाप्त होने के एक दिन बाद और शराब नीति मामले में उनसे पूछताछ के लिए ईडी की तारीख से एक दिन पहले वह कोर्स के लिए एक अज्ञात स्थान पर गए। अधिकारियों ने कहा कि केजरीवाल हर साल 10 दिवसीय विपश्यना कोर्स के लिए जाते हैं और इस साल वह 19 से 30 दिसंबर तक ऐसा करेंगे। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा भेजे गए समन के समय पर मंगलवार को सवाल उठाया और दोहराया कि आबकारी नीति मामला फर्जी है। ईडी द्वारा आप प्रमुख को 21 दिसंबर को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहे जाने के बारे में पूछे जाने पर पार्टी ने कहा कि उसकी कानूनी टीम एजेंसी के नोटिस का जवाब देगी।

मध्यप्रदेश विधानसभा के नरेंद्र सिंह तोमर अध्यक्ष चुने गये

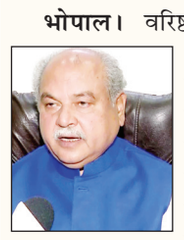

भोपाल। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बुधवार को सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। नवनिर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को 66 वर्षीय तोमर को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने का प्रस्ताव रखा, जिसका विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने समर्थन किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी तोमर को स्पीकर चुने जाने का प्रस्ताव रखा, जिसका पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल ने समर्थन किया। विपक्षी कांग्रेस विधायक अजय सिंह, जयवर्धन सिंह और राजेंद्र कुमार सिंह सहित पांच और प्रस्ताव भी तोमर के पक्ष में पेश किये गये। प्रस्ताव के ध्वनि मत से पास होने के बाद अस्थायी अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) गोपाल भार्गव ने तोमर को सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष घोषित किया।

उपराष्ट्रपति का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान

एनडीए के सांसद उपराष्ट्रपति के सम्मान और कल्याण बनर्जी के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया

नईदिल्ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के अपमान पर एनडीए गठबंधन की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। एनडीए के सांसद उपराष्ट्रपति के सम्मान और टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धनखड़ के सम्मान में एनडीए के सदस्य राज्यसभा की कार्यवाही में एक घंटे तक खड़े रहेंगे। एनडीए के नेताओं का कहना है कि यह विपक्ष की ओर से संविधान पद का घोर अपमान किया गया है। उनकी कहना है कि पहली बार किसी जाट समाज के नेता और किसान पुत्र को यह संवैधानिक पद मिला है, जिसका विपक्ष के नेताओं ने अपमान किया है।

सदन की कार्यवाही के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि विपक्ष ने उपराष्ट्रपति का ही नहीं देश के संविधान का भी अपमान किया है। उन्होंने कहा कि इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जोशी ने कहा कि ओबीसी समाज का ऐसा अपमान करना कहीं से भी उचित नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि संविधान की गरिमा को भंद करना विपक्षी नेताओं की आदत सी हो गई है। उन्होंने कहा कि 20 साल तक विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी का अपमान किया। अब उपराष्ट्रपति का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।

20 साल से मैं भी सह रहा हूं अपमान : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फोन किया और संसद परिसर में कुछ सांसदों के व्यवहार पर निराशा व्यक्त की। यह घटनाक्रम मंगलवार को उस समय राजनीतिक विवाद पैदा होने के एक दिन बाद सामने आया है जब संसद की सीढ़ियों पर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान तृणमूल कांग्रेस नेता कल्याण बनर्जी ने धनखड़ का उपहास किया था। सांसद अपने निलंबन का विरोध कर रहे थे, जिसकी सत्तारूढ़ भाजपा ने कड़ी निंदा की थी।

एक्स पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का टेलीफोन कॉल प्राप्त हुआ। उन्होंने पवित्र संसद परिसर में कुछ माननीय सांसदों की घृणित नाटकीयता पर बहुत दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पीएम ने मुझे बताया कि वह पिछले बीस वर्षों से इस तरह के अपमान सह रहे हैं, लेकिन यह तथ्य कि उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर और वह भी संसद में ऐसा हो सकता है, दुर्भाग्यपूर्ण है।

इसके जवाब में उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि ऐसी घटनाएं उन्हें अपना कर्तव्य निभाने से नहीं रोकेंगी।

उपराष्ट्रपति ने बतया कि मैंने उनसे कहा- श्रीमान प्रधान मंत्री, कुछ लोगों की हरकतें मुझे अपना कर्तव्य निभाने और हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों को बनाए रखने से नहीं रोकेंगी। मैं तहे दिल से उन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूं। कोई भी अपमान मुझे अपना रास्ता बदलने पर मजबूर नहीं करेगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारे जाने के बाद विपक्ष पर निशाना साधते हुए मंगलवार को दावा किया कि 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस' यानी 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं की, पिछड़े और साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान करने की परंपरा रही है।

संसद के दोनों सदनों से विपक्षी सदस्यों के निलंबन पर विरोध जताते हुए विपक्ष के सांसदों ने मंगलवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया और सदन की 'मॉक कार्यवाही' का आयोजन किया जिस दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी। निलंबित सांसदों ने संसद के नए भवन के 'मकर द्वार' पर धरना दिया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्य बनर्जी ने राज्यसभा की कार्यवाही के संचालन के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ के बोलने की शैली की नकल उतारी। मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी खड़े थे और वह मोबाइल फोन से बनर्जी द्वारा धनखड़ की नकल उतारे जाने का वीडियो बनाते देखे गए।

क्या दलित होने की वजह से संसद में बोलने नहीं दिया जाता: खरगे

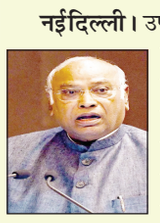

नईदिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने का मामला गंभीर होता चला जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी समेत पूरा एनडीए दल इसका विरोध कर रहा है वहीं, विपक्ष भी इसपर प्रतिक्रिया कर रही है। इसी बीच कांग्रेस प्रमुख का बयान भी आया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को कहा कि जाति को हर मुद्दे में नहीं घसीटा जाना चाहिए। उन्होंने साथ ही यह सवाल भी किया कि क्या उन्हें हर बार राज्यसभा में बोलने की अनुमति नहीं मिलने पर यह कहना चाहिए कि दलित होने के कारण ऐसा हुआ है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद परिसर में उनकी, तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद द्वारा नकल उतारे जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उच्च सदन में कहा कि संसद परिसर में उनकी नकल उतारकर किसान समाज और उनकी जाति (जाट) का अपमान किया गया है। मल्लिकार्जुन खरगे ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सभापति का काम दूसरे सदस्यों को संरक्षण देना है लेकिन वह खुद इस तरह का बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा, ''मुझे अक्सर राज्यसभा में बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। क्या मुझे यह कहना चाहिए कि मैं दलित हूं।।। इसलिए... उन्हें जाति के नाम पर बोल कर लोगों को नहीं भड़काना चाहिए।'' कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह देश के लिए बहुत दुखद दिन है जब संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अपनी जातियों के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार यह मुद्दा उठाकर संसद की सुरक्षा में सेंध के मुद्दे से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पूछा कि क्या अब हर किसी को अपनी जाति बताने वाला ठप्पा लगा कर घूमना चाहिए? मल्लिकार्जुन खरगे ने सवाल किया कि संसद की सुरक्षा में सेंध के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों में कुछ भी नहीं कहा लेकिन संसद के बाहर उन्होंने अपनी बात रखी तो

141 सांसदों के निलंबन पर बोलीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष

लोकतंत्र का गला घोंटा गया हम डरेंगे नहीं: सोनिया गांधी

नईदिल्ली। संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में इसकी निंदा की गई। कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) प्रमुख सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव परिणाम पार्टी के लिए बेहद निराशाजनक रहे। सोनिया ने कहा कि भारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं लेकिन हमें विश्वास है कि हमारा धैर्य,हमें सफलता दिलाएगा। हमारी विचारधारा और मूल्य हमारे मार्गदर्शक हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ माह में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। पार्टी के और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के सदस्य के तौर पर हमें कठिन परिश्रम करना है।

कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि विविधता भारत की ताकत है, भाजपा ने एकता की इस भावना को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि संसद के विपक्षी सदस्यों ने 13 दिसंबर की असाधारण घटनाओं को संबोधित करते हुए लोकसभा में गृह मंत्री द्वारा दिया जाने वाला एक बयान मांगा था। इस अनुरोध के साथ जिस अहंकार के साथ व्यवहार किया गया उसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस सत्र में जम्मू-कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू जैसे महान देशभक्तों को बदनाम करने के लिए इतिहास को विकृत करने और ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने वाले लोग लगातार अभियान चला रहे हैं।

सोनिया ने कहा कि इन प्रयासों में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने खुद मोर्चा संभाला है, लेकिन हम डरेंगे या झुकेंगे नहीं। हम सच बोलने पर कायम रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि महिला आरक्षण विधेयक को इस शर्त के साथ पारित किया जाना कि इसे केवल परिसीमन या जनगणना के बाद ही लागू किया जाएगा, महिलाओं को गुमराह करने और उनके वोट हासिल करने के इरादे से किया गया एक दिखावा है, जबकि उन्हें जो हक मिला है, उससे पीछे हटना है। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लंबे समय से अपेक्षित है। बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि महिलाओं के लिए आरक्षण तुरंत लागू किया जाना चाहिए और इसमें ओबीसी समुदाय सहित सभी समुदायों की महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए।

राहुल वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया होता तो आपको पता नहीं चलता

नईदिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक हुई। तृणमूल प्रतिनिधिमंडल ने सांसद कल्याण बनर्जी को इस बैठक से बाहर रखा। बुधवार को ममता समेत 11 तृणमूल सांसदों ने राज्य की विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की। लेकिन कल्याण बनर्जी उस टीम में नहीं थे। हालांकि, मोदी से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा, कल्याण बनर्जी ने जो किया मेरा संसदीय दल इसका जवाब दे सकता है। वे निर्णय लेने के लिए पर्याप्त हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। तृणमूल सांसद मिमिक्री विवाद पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, ...अगर राहुल ने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया होता तो आपको पता नहीं चलता।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मैच आज

पार्ल। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 21 दिसंबर यानी कि गुरुवार को खेला जाएगा। दोनों ही टीम इस सीरीज में एक-एक की बराबरी पर है। ऐसे में तीसरे मैच को जीतने वाली टीम ट्रॉफी को अपने नाम कर लेगी। भारतीय टीम ने सीरीज का पहला मुकाबला जीता था। जबकि दूसरे में दमदार वापसी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को पटखनी दी।

केएल राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम तीसरे मुकाबले को जीतना चाहेगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे यानी की फाइनल मुकाबले में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। वनडे सीरीज के पहले मैच को भारत ने 8 विकेट से अपने नाम किया था। जबकि दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे मैच को 8 विकेट से जीत कर ही हिसाब बराबर कर दिया।

भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज साईं सुदर्शन ने दोनों ही मैचो में अर्धशतक जड़कर सबको खासा प्रभावित किया। साईं सुदर्शन भारत की तरफ से इस सीरीज में डेब्यू करते नजर आए। उन्होंने अपने डेब्यू मुकाबले में भी अर्धशतक जड़ा था। जबकि दूसरे मैच में उन्होंने बैक टू बैक 50 रन बनाकर अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया।

पार्ल शहर के बौलेंड पार्क स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आमने-सामने होगी। पोलैंड पार्क स्टेडियम के पिच की बात करें तो यहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलती रही है। तेज गेंदबाजों के अलावा यहां बल्लेबाजों के लिए भी काफी कुछ है। इस स्टेडियम में अब तक कुल 20 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं। जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 9 दफा जीत हासिल की है। जबकि बाद में बैटिंग करने वाली टीमों को 10 बार कामयाबी मिली है। ऐसे में टॉस इस मुकाबले पर ज्यादा फर्क नहीं डालेगी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 931 अंक टूटा निफ्टी 21,100 के करीब

नईदिल्ली। घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को भारी उतार-चढ़ाव रहा। आज के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 931 अंक कमजोर हुआ। वहीं, निफ्टी में भी 347 अंक की भारी गिरावट दर्ज की गई। व्यापक बाजारों में, क्रमश: मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में क्रमश: 3.3 प्रतिशत और 3.5 प्रतिशत की भारी गिरावट आई। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 930.88 अंक यानी 1.30 फीसदी की भारी गिरावट के साथ 70,506.31 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 70,302.60 और 71,913.07 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 346.70 अंक यानी 1.62 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। यह 26 अक्टूबर 2023 के बाद निफ्टी में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। निफ्टी दिन के अंत में 21,106.40 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 21,087.35 और 21,593.00 के रेंज में कारोबार हुआ।

पहली छमाही में सीपीएसई का कैपिटल एक्सपेंडीचर 3.79 लाख करोड़ रुपये

नईदिल्ली। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) का पूंजीगत व्यय चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 3.79 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। यह बजट लक्ष्य का 52 प्रतिशत है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। इससे पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में सीपीएसई का पूंजीगत व्यय बजट लक्ष्य का 43 प्रतिशत यानी 2.85 लाख करोड़ रुपये रहा था। वित्त मंत्रालय ने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, ''सितंबर, 2023 तक सीपीएसई का पूंजीगत व्यय बजट लक्ष्य का 51.71 प्रतिशत रहा है।'' पूरे वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीपीएसई का पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 7.33 लाख करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2022-23 में पूरे साल के लिए सीपीएसई का पूंजीगत व्यय अनुमानत: 6.62 लाख करोड़ रुपये रहा है।

ब्लैकस्टोन ने समूची हिस्सेदारी 7,100 करोड़ रुपये में बेची

नईदिल्ली। वैश्विक कोष ब्लैकस्टोन ने शेयर बाजारों में थोक सौदे में एम्बैसी ऑफिस पार्क्स रीट में अपनी समूची 23.5 प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग 7,100 करोड़ रुपये में बेच दी है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने अपनी यूनिट करीब 316 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेची हैं। कुछ मौजूदा यूनिटधारकों ने इसमें भाग लिया है। उन्होंने बताया कि एसबीआई म्यूचुअल फंड एक नया निवेशक है। एम्बैसी ऑफिस पार्क रीट भारत का पहला रियल एस्टेट निवेश न्यास (रीट) है जो वैश्विक निवेश फर्म ब्लैकस्टोन और बेंगलुरु स्थित रियल्टी फर्म एम्बैसी समूह द्वारा प्रायोजित है। सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से लगभग 5,000 करोड़ रुपये जुटाने के बाद इसे 2019 में सूचीबद्ध किया गया था। पिछले साल ब्लैकस्टोन ने एम्बैसी ऑफिस पार्क्स रीट में अपने शेयर बेचकर लगभग 32.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग 2,650 करोड़ रुपये) जुटाए थे।

रैंसमवेयर अटैक की चपेट में एचसीएल टेक्नोलॉजीज

नईदिल्ली। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने बुधवार को कहा कि उसकी एक परियोजना एक अलग क्लाउड वातावरण में रैंसमवेयर हमले से प्रभावित हुई थी और इसका कारण समझने के लिए जांच चल रही थी। एक नियामक फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि वह आवश्यकतानुसार उपचारात्मक कार्रवाई करेगी। कंपनी ने कहा, आपको सूचित किया जाता है कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज को अपने एक प्रोजेक्ट के लिए एक अलग क्लाउड वातावरण में रैंसमवेयर हमले के बारे में पता चला है। इस घटना के कारण ओवरऑल एचसीएल टेक्नोलॉजीज नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं देखा गया है। कंपनी ने आगे कहा, साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन एचसीएल टेक्नोलॉजीज के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पूंजी निवेशक मालामाल, कम कमाई वालों का जीना मुहाल

अनिल तिवारी

भारतीय शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक का छोटी मोटी गिरावट के बावजूद 71 हजार के ऊपर के रिकॉर्ड स्तर पर रहना इस बात का संकेत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों का भरोसा कायम है। थोड़े उतार-चढ़ाव के साथ बाजार में चहल-पहल है, बेंचमार्क इंडेक्स का प्रदर्शन भी संतोषजनक बताया जा रहा है लेकिन करीब दो महीने पहले बाजार में आम उपभोक्ता वस्तुओं की खुदरा कीमतों में गिरावट की वजह से आम लोगों को जो राहत मिली थी वह एक बार फिर छिनती हुई दिख रही है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक खाने-पीने की वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी की वजह से खुदरा महंगाई दर पिछले तीन महीने के उच्च स्तर यानी 5.5 प्रतिशत पर पहुंच गई है। आटा, दाल, नमक, तेल, चावल आदि के लगातार बढ़ते दामों से कम कमाई पर गुजर-बसर करने वालों का जीवन और अधिक कठिन होता जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि बीते अगस्त महीने से खाद्य वस्तुओं के दाम में कमी आने की वजह से महंगाई दर में लगातार कमी दर्ज की जा रही थी। यही कारण है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई अक्टूबर के महीने में 4.57 प्रतिशत पर आ गई थी। दिसंबर के पहले पखवाड़े में बाजारी कारोबार के बढ़ने के चलते शेयर के भाव तो उंचे चढ़ते गए, पर महंगाई डायन भी अपना डायना फैलाने लगी।

वर्तमान में महंगाई दर 5.5 प्रतिशत आंकी गई है। हालांकि यह रिजर्व बैंक की ओर से तय अधिकतम सीमा के दायरे में ही है, लेकिन यह महंगाई की ओर रेखांकित

करने वाली सीमा रेखा के करीब भी है। मालूम हो कि वस्तुओं की खुदरा कीमतें इस स्तर पर पहुंचने के बाद एक बड़ी आबादी खाने-पीने तक को लेकर अपने हाथ समेटने लगती है। हालांकि माना जाता है कि ठंड के मौसम की शुरुआत के बाद खासतौर पर बाजार में सब्जियों की आमद बढ़ने की वजह से कीमतों में कमी आती है लेकिन ताजा आंकड़े इसके अनुकूल नहीं दिखाई दे रहे हैं।

यह सही है कि करीब तीन साल पहले कोरोना महामारी की वजह से जो हालात पैदा हुए उससे उबरने में देश को काफी समय लगा और अब भी कई क्षेत्र खुद को संभालने की लगातार कोशिश में है। बहुत सारे मामलों में बाजार में सहजता आई है और इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर भी देखने में आया है। निवेशकों के भरोसे के कारण शेयर बाजार की उड़ान इसी का नतीजा है। कमजोर वैश्विक आर्थिक संकेतों के बावजूद भारत में शेयर बाजारों के सूचकांक हौसला देने वाले हैं। चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह से दुनिया के निवेशक अब चीन की जगह भारत को प्राथमिकता दे रहे हैं। भारत में बेचें-चीन में खरीदे की रणनीति में बदलाव लाते हुए विदेशी निवेशकों ने भारत में खरीदे और चीन में बेचें को महत्व देना शुरू कर दिया है। इसके अलावा विदेशी निवेशक विकसित दुनिया के देश खासकर अमेरिका भारत को चीन प्लस वन नीति का प्रमुख साझेदार मानते हैं। चीन के प्रति बदलती धरणा ने भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी संस्थागत निवेश (एफपीआई) के प्रवाह को गति दी है। इस वर्ष के पहले दो महीनों में लगभग 35,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचने वाले एफपीआई बड़े पैमाने पर अब खरीदार बन गए और मई के बाद से अब तक सवा लाख करोड़ रुपए से अधिक के शेयर खरीदार बन गए। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक वर्ष 2023-24 के लिए मुद्रा स्फीति 5.1% अनुमानित है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बदलाव के कारण डॉलर के मुकाबले रुपया अभी भी कमजोर बना हुआ है। अगला साल चुनावी साल है इसलिए मौद्रिक नीतियों के कठोर होने की संभावना ना के बराबर है, फिर भी स्थिरता को बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रण में रखने के लिए फौरी कदम उठाने ही चाहिए। इन सबके बावजूद समग्र आर्थिक सूचक भारतीय अर्थव्यवस्था की दूरगामी संभावनाओं की गुलाबी तस्वीर पेश कर रहे हैं।

उपराष्ट्रपति का उपहास उड़ाने से भाजपा में रोष आज राहुल का पुतला दहन करेगी

रायपुर। भारत की संसद के बाहर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने और उपहास उड़ाने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है जहां एक ओर जानकर इस कृत्य को खासा अव्यावहारिक बता रहे हैं वहीं भारतीय जनता पार्टी भी तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी और कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी के इस कृत्य पर खासा रोष व्यक्त कर रही है आपको बता दें की मंगलवार को संसद भवन के सामने तृणमूल कांग्रेस के नेता द्वारा उपराष्ट्रपति की नकल उतार कर उपहास उड़ाया जाता है और कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी इस हरकत का लाइव वीडियो बनाते है और इस कृत्य में सहयोगी की तरह खड़े रहते हैं ।

इस विषय को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है साथ ही भाजपा नेताओ में खासा रोष व्याप्त है इस विषय को लेकर भाजपा के जिला कार्यालय में एक आवश्यक बैठक की गई जिला अध्यक्ष जयंती पटेल ने कहा की यह कृत्य ना केवल आसंसदीय और उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है अपितु अव्यावहारिक भी है जगदीप धनखड़ भारतीय राजनीति के वरिष्ठ नेता है एवं पूर्ण सम्मान के हकदार हैं विपक्ष में रहकर विरोधाभास होना स्वाभाविक है परंतु इस तरह की स्तरहिनता किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा आज बुलाई गई इस आवश्यक बैठक का मुख्य उद्देश्य है पुतला दहन राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी के अव्यावहारिक कृत्य का सांकेतिक जवाब देने हेतु हम कल अर्थात गुरुवार दोपहर 3 बजे धरना स्थल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन करेंगे जिससे यह संदेश भी पहुंचे की भारत के उच्च पदों की गरिमा का मर्दन करने उसका उपहास उड़ाने पर भाजपा कार्यकर्ता ऐसे कृत्यों का हर मंच से माकूल जवाब देगा।

जिला मीडिया प्रभारी वंदना राठौड ने पुतला दहन को लेकर आहूत बैठक संबंधित पूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि आज जिला भाजपा कार्यालय में आहूत बैठक में मंच संचालन जिला महामंत्री रमेश सिंह ठाकुर ने किया एवं आभार प्रदर्शन सत्यम दुवा द्वार किया गया बैठक प्रमुख रूप से जिला भाजपा अध्यक्ष जयंती पटेल अकबर अल, श्यामाप्रसाद चक्रवर्ती, गोपी साहू, मनीषा चंद्राकर, तुषार चोपड़ा, हरीश सिंह, खेमकुमार सेन, राजीव मिश्रा, जितेंद्र गोलछा, राहुल राय, अनिल बाघ , तोषण साहू, गोरेलाल नायक, बी.श्रीनिवास राव , प्रीतम ठाकुर , संतोष साहू, सुनील कुकरेजा , अनूप खेलकर, ओमप्रकाश साहू , संदीप जंघेल, विकास सेठिया, रमेश शर्मा, राजू बिरनानी, प्रीतम महानंद, संजय सिंह, आशीष धनगर, अभिषेक तिवारी, विजय साहू, कुबेर राम सपहा, रमेश शर्मा, अखिलेश पवार, जीवन साहू, सुधीर चौबे सहित बड़ी संख्या में रायपुर शहर जिला के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

रायपुर। विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह की अध्यक्षता में यहां विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महंत, उपमुख्यमंत्री द्वय श्री अरुण साव और श्री विजय शर्मा सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे

छग शासन ने विधायक निधि का 118.80 करोड़ किया जारी

रायपुर। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना विधायक निधि) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के शेष बजट की एक तिहाई राशि 118 करोड़ 80 लाख रूपए छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधानसभा के लिए संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा आज जिलों को आवंटित कर दी गई है.

राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को इस राशि का उपयोग प्रतिमाह समानुपातिक व्यय की सीमा के अधीन मार्च 2024 तक किए जाने के निर्देश दिए गए है। योजना के तहत आकस्मिक व्यय की राशि पूर्व के बजट आवंटन में जारी की जा चुकी है. उक्त आवंटित राशि में आकस्मिक व्यय की राशि शामिल नहीं है. उल्लेखनीय है कि योजना अंतर्गत बजट की दो तिहाई राशि का आबंटन मई 2023 में ही जिलों को किया जा चुका है.

किस विस क्षेत्र को मिली कितनी मिली रकम

- आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा पत्र के अनुसार कोरिया, सरगुजा, जशपुर, धमतरी, बालोद, बेमेतरा, कांकेर, बस्तर जिले को पृथक-पृथक रूप से 3 करोड़ 96 लाख रूपए.
- दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर को पृथक-पृथक रूपए से 1 करोड़ 32 लाख रूपए.
- गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को 1 करोड़ 58 लाख 40 हजार रूपए.
- कोण्डागांव, कबीरधाम और गरियाबंद को पृथक-पृथक रूप से 2 करोड़ 64 लाख रूपए.
- दुर्ग, राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा जिले को पृथक-पृथक रूप से 7 करोड़ 92 लाख रूपए.
- कोरबा, महासमुंद, बलौदाबाजार को पृथक-पृथक रूप से 5 करोड़ 28 लाख रूपए.
- सूरजपुर और बलरामपुर जिले को को पृथक-पृथक रूप से 3 करोड़ 30 लाख रूपए.
- रायगढ़ जिले को 6 करोड़ 60 लाख रूपए.
- बिलासपुर जिले को 7 करोड़ 12 लाख 80 हजार रूपए.
- मुंगेली जिले को 3 करोड़ 16 लाख 80 हजार रूपए और राजधानी रायपुर जिले के 9 करोड़ 24 लाख रूपए के राशि आबंटित की गई है.

राजधानी में गोली बारी भाजपा के जंगल राज की धमक - कांग्रेस

प्रदेश में एक बार फिर वहीं आतंक का दौर वापस आ गया

रायपुर। राजधानी रायपुर में एक युवक को सरेआम गोली मारे जाने की कांग्रेस ने कड़ी निंदा करते हुये चिंता व्यक्त किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राजधानी में गोली बारी भाजपा के जंगल राज की धमक है। बेहद ही दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने अभी एक हफ्ता नहीं हुये है प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गये है अपराधी बेलगाम हो चुके है सरेआम लोगो की हत्याएं की जा रही है गोलियां चल रही है।

प्रदेश में एक बार फिर वहीं आतंक का दौर वापस आ गया है जो 2018 के पहले था गोलियां मार कर लोगो को लूटा जाता था अपराधी पकड़े नहीं जाते थे एक बार फिर से गोलिया चलायी गयी है अपराधी बैखोफ हो कर घूम रहे है यह भारतीय जनता पार्टी की जंगलराज है जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फिर से वापस आ गया है।

शुक्ला ने कहा कि नई सरकार सत्ता प्राप्ति का मौज मना रही भाजपा के चुने हुये विधायक नेता सरकार में अपनी भागीदारी जुगत लगाने में लगे हुये हैं आपसी गुटबाजी के कारण मंत्री मंडल का गठन नहीं हो पा रही है। एक हफ्ते में ही भाजपा की नई सरकार बेचारी और दिग्भ्रमित दिखने लगी है जिसके कारण अपराधी और अराजकतत्व फिर सर उठाने लगे है। राज्य में नक्सल गतिविधियां बढ़ गई है, अपराधी सरेआम गोलियां चला रहे है यह स्थिति राज्य के नागरिको के लिये चिंता पूर्ण है।

अनुपूरक बजट को लेकर अग्रवाल का बयान, कहा-

बजट आएगा तब कांग्रेस के लोग जमीन पर लौटने लगेंगे

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 12992 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट का प्रस्ताव रखा। इस बजट में पीएम आवास के लिए 3799 करोड़,धान पर बोनस के लिए 3800 करोड़ और महतारी वंदन के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुपूरक बजट पर कल विधानसभा में चर्चा होगी, जिसके हंगामेदार होने के आसार हैं। वहीं इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार को दिशाहीन बताया। उन्होंने कहा कि अनुपूरक में 18 लाख आवास के लिए राशि दिखाई नहीं दे रही हैं। थोड़ी बहुत राशि 2 साल के बकाया बोनस की है। बोनस कितना मिलेगा क्या मिलेगा पता नहीं है। ऋण माफी पर सब अलग-अलग बोल रहे हैं, कुछ क्रांतिकारी फैसले के लिए बजट में प्रावधान नहीं है। इस पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आज जो बजट आया उसमें मोदी की गारंटी , मातृ वंदन योजना के लिए , पीएम आवास के लिए और धान खरीदी के लिए पैसा रखा गया है । यह पहली सरकार है जिसने बनते ही मोदी की गारंटी बात की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बजट आएगा तब आप देखिएगा कांग्रेस के लोग जमीन पर लौटने लगेंगे।

किरणमयी ही रहेंगी महिला आयोग की अध्यक्ष, कोर्ट से मिली राहत

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक को हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है। किरणमयी नायक फिलहाल पद पर बनी रहेंगी। अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट ने किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। दरअसल, प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने एक पत्र जारी कर सभी निगम मंडल और आयोग के अध्यक्ष को तत्काल पद से मुक्त करने का आदेश जारी किया था। चूंकि महिला आयोग की अध्यक्ष का कार्यकाल तीन साल का होता है और छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद किरणमयी नायक को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने अपना एक कार्यकाल पूरा कर लिया। इसके बाद जुलाई 2023 में ही उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था। लिहाजा इसी आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश को महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी, जिस पर आज सुनवाई करते हुए जस्टिस एएनके चंद्रवंशी के सिंगल बेंच ने किरणमयी नायक को फौरी राहत दी है और अगली सुनवाई तक किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। इस स्थिति में फिलहाल किरणमयी नायक छग राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर बनी रहेंगी। मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।

10 को होगी अगली सुनवाई

साय के इस्तीफा पर केदार का तंज, कहा- तोड़ने में भरोसा करने वाली कांग्रेस खुद टूट रही

रायपुर. वरिष्ठ आदिवासी नेता नंदकुमार साय के कांग्रेस से इस्तीफा देने पर छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा महामंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया है. केदार कश्यप ने कहा कि, तोड़ने में भरोसा करने वाली कांग्रेस खुद टूट रही है. कांग्रेस में भले लोगों का कोई काम नहीं है. महंत रामसुंदर दास जी के साथ कांग्रेस ने राजनीति की. पूरे प्रदेश में सर्वाधिक अंतर से हार के बाद उन्हें कांग्रेस के भीतर का घटिया खेल समझ में आ गया तो उन्होंने कांग्रेस त्याग दी. कई और वरिष्ठ कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़ दी. अब वरिष्ठ आदिवासी नेता नंदकुमार साय ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है. यह कांग्रेस की अंतर्कथा का प्रमाण है. आगे केदार कश्यप ने कहा, नंदकुमार साय जी को भूपेश बघेल कांग्रेस में ले तो गए, लेकिन उन्हें यथोचित सम्मान नहीं दिया.

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

भाजपा का वादाखिलाफी की ओर बढ़ता कदम - शर्मा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ हो चुकी है पर वादे पूरे करने के मामले में हिला हवाला शुरू हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार की नीयत में खोट नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी चालू है पूर्ववर्ती सरकार ने बीस क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी का आदेश कर दिया था तदानुसार धान खरीदी हो रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने का आश्वासन किसानों को दिया है, जो किसान 20 क्विंटल बेच चुका है और उसके पास एक एकड़ ही खेती है तो क्या बाद में वह एक क्विंटल धान बेचने सोसायटी जाएगा? और अगर गया तो उसके व्यय भार की क्षति पूर्ति कैसे होगी। इसलिए तत्काल 21 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी करने का आदेश जारी करे। इसी तरह एकमुश्त 3100 के भाव से भुगतान का वादा है उसे भी अविलंब पूरा करना चाहिए। दो साल का बकाया बोनस देने का भी आश्वासन है यह राशि सात साल पहले की है बहुत से किसान दिवंगत हो चुके हैं और उनका खाता भी बंद हो चुका है उनके उत्तराधिकारियों को भुगतान सुनिश्चित करने का प्रावधान भी करना होगा समय से पहले हम सज्ञान में ला रहें हैं ताकि बाद में भाजपा सरकार यह न कहे की यह बात हमारे ध्यान में नहीं थी। शर्मा ने कहा कि वादे देख लिये अब इरादे और क्रियान्वयन भी देखना है।

धान बोनस वितरण के संबंध में मुख्य सचिव ने कलेक्टरों की वीडियों कॉन्फ्रेंस से ली बैठक

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से राज्य के संभागायुक्त एवं कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक ली। बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी के परिपालन में राज्य के किसान भाईयों के बकाया धान बोनस की राशि के भुगतान और विकसित भारत यात्रा संकल्प यात्रा और प्रधान मंत्री आवास योजना के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने आगामी 25 दिसम्बर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित सुशासन दिवस की तैयारियां और घोषणा पत्र के परिपालन में दो वर्ष के बकाया धान बोनस राशि वितरण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा है कि धान बोनस वितरण का कार्यक्रम नई सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता के लिए जिला अधिकारियों को पूरी सर्तकता, गंभीरता एवं तत्परता से कार्य करने कहा है। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए जरूरी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि छत्तीगसढ़ में 18 लाख हितग्राहियों लाभान्वित किया जायेगा।

छग जिला खनिज संस्थान न्यास नियम के क्रियान्वयन के संबंध में जारी निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ खनिज साधन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम-15 के क्रियान्वयन के संबंध में आज मंत्रालय से नये दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिसके तहत जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद द्वारा ऐसे कार्य जिन्हें प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, परंतु कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं, ऐसे अप्रारंभ कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 5 अनुसार जिला खनिज सस्थान न्यास का उद्देश्य खनन अथवा खनन से संबधित संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्ति एवं क्षेत्र के हित एवं लाभ के लिए ऐसी रीति से कार्य करना है नियम-22 अनुसार न्यास निधि का उपयोग किये जाने का प्रावधान है। न्यास की गतिविधियों के सफल संचालन के लिए समय-समय पर राज्य शासन द्वारा विभिन्न निर्देश जारी किये गये हैं, जिनके तारतम्य में आज खनिज विभाग द्वारा नये निर्देश जारी किए गए हैं। समस्त कलेक्टर-सह-अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास को छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम-10. 11 एवं 12 (1) के संदर्भ में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है।

7 वर्ष की मासूम अंजनी बनी बाल आरक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सौपा नियुक्ति आदेश

दुर्ग। दुर्ग जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग ने आज 7 साल की मासूम अंजनी भट्ट को बाल आरक्षक के पद पर नौकरी का नियुक्ति आदेश प्रदान किया. इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अबोध बालिका अंजनी से आत्मीयता के साथ बातचीत कर उसका हाल जाना. बता दें कि बाल आरक्षक के रुप में भर्ती की गई बच्ची के पिता की असामयिक निधन के बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति दी गई है. बता दें कि अंजनी भट्ट आज अपनी मां के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची थी, बच्ची को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बालक के सिर पर हाथ फेरा और उसे बताया कि अब आप भी पुलिस बन गए हो. उनके आत्मीय व्यवहार और अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए अंजनी के स्वजनों ने भी आभार जताया. वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दिवंगत आरक्षक अतुल भट्ट के आकस्मिक निधन पर परिवार के सदस्यों से मिलकर सांत्वना दी और परिवार को किसी भी प्रकार की आवश्यकता में दुर्ग पुलिस से सहयोग प्रदान करने के लिए आश्वास्त किया.

आलपरस में एक इनामी नक्सली गिरफ्तार, कई अपराधों को दे चुका है अंजाम

कांकेर । बीएसएफ एवं जिला पुलिस बल डीआरजी की संयुक्त टीम नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर नक्सली ग्रस्त सर्चिंग के लिए निकली हुई थी। वहीं, पुलिस टीम द्वारा ग्राम आलपरस के पास 10 वर्षों से सक्रिय माओवादी जनताना सरकार अध्यक्ष सुंदर दुगा को गिरफ्तार किया है। सुंदर दुगा कोयलीबेडा थाना क्षेत्र में हुए अपराधों में शामिल था। जैसे कि मजदूरों के साथ मारपीट, वाहनों में आगजनी, ब्लास्ट, सुरक्षा बलों से हथियार लूटने और जानमाल का नुकसान पहुंचाने की नीयत से फायरिंग, आईडी विस्फोट किया जाना। दुगा कई अपराधों में शामिल था, जिसे गिरफ्तार कर न्यायलय मे पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

मोर रायपुर एप्प में टो-व्हीकल ट्रैकिंग और व्हीकल इन्फारमेशन टैग सुविधाएं शुरू होंगी

मोवा ओवरब्रिज पर दोनों तरफ बनेंगे डिवाइडर, सिग्नलों पर जाम से मिलेगी निजात

रायपुर। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में रायपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए जरूरी उपायों पर विशेष रूप से चर्चा की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल और नगर निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में मोवा ओवरब्रिज पर दोनों ओर 50-50 मीटर डिवाइडर बनाने पर सहमति हुई। इस ब्रिज पर दोनों तरफ के चौराहों पर रेड सिग्नल की स्थिति में बड़ी संख्या में वाहन बेतरतीब तरीके से रूकने के कारण जाम की स्थिति बनती है।

दोनों तरफ 50-50 मीटर डिवाइडर बन जाने से सिग्नल रेड होने पर वाहन चालक व्यवस्थित रूप से अपनी-अपनी तरफ रूकेंगे और जाम की स्थिति से निजात मिलेगी। इस बैठक में एडीएम श्री एन आर साहू, डीएसपी ट्रैफिक श्री गुरजीत सिंह, एसडीएम देवेन्द्र पटेल सहित लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में भाटागांव चौक से लेकर काठाडीह चौक हनुमान मंदिर और अवंती बाई चौक से क्रिस्टल आर्केड तक डिवाइडर बनाने अथवा सड़क को दाहिने-बाएं ट्रैफिक के लिए बीच से विभाजित करने मार्कर आदि लगाने पर भी विचार किया गया।

इसी प्रकार सघन आबादी क्षेत्र पचपेड़ी नाका से सरोना ओवरब्रिज तक भी डिवाइडर को तीन फीट ऊंचा करने की भी जरूरत बतायी गई। कलेक्टर डॉ. भुरे ने इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

कलेक्टर ने शंकर नगर रोड, मालवीय रोड, एमजी रोड, बिलासपुर रोड, पुरानी बस्ती और कटोरा तालाब रोड पर विशेष रूप से दुकान के बाहर सामान निकालकर रखने और दुकानदारी करने वाले व्यापारियों तथा ठेले-खोमचों वालों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

लॉन टेनिस प्रतियोगिता के टीम मुकाबले में रायपुर रीजन बनी विजेता

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी की तीन दिवसीय अंतरक्षेत्रीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता के टीम मुकाबले में कोरबा पश्चिम की टीम को 3 - 0 से हराकर रायपुर रीजन ने खिताब अपने नाम किया। दूसरे दिन ओपन एकल तथा युगल स्पर्धाएं भी हुईं। इसमें ओपन सिंगल्स के क्वाटर फाइनल तथा डबल्स के सेमीफाइनल मैच खेले गए हैं। अब प्रतियोगिता के तीसरे और अंतिम दिन युगल स्पर्धा के फाइनल एवं एकल स्पर्धा के सेमीफाइनल तथा फाइनल मैच खेले जाएंगे। टीम स्पर्धा के विजेता रायपुर रीजन का प्रतिनिधित्व आर के बंछोर,एहतेशाम, पवन ओगले , शेखर वर्मा एवं टोमन दिल्लीवार ने किया। लॉन टेनिस प्रतियोगिता प्रभारी श्री मनोज वर्मा ने बताया कि तीन दिवसीय प्रतियोगिता का समापन गुरूवार को होगा । 19 से 21 दिसंबर तक युनियन क्लब रायपुर में आयोजित प्रतियोगिता में प्रदेश की 7 क्षेत्रीय टीमों रायपुर रीजन, रायपुर सेंट्रल, बिलासपुर रीजन ,दुर्ग रीजन ,राजनांदगांव रीजन, कोरबा पूर्व और कोरबा पश्चिम के 40 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.